अमर उजाला
प्रवाह
महोत्सव विश्वास का 75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948
नई दिल्ली ■ मंगलवार, 27 फरवरी 2024

समय लोगों को बदल देता है, लेकिन वह उनकी छवि नहीं बदलता, जो हमने उनके बारे में बना रखी है। -मार्सेल प्राउस्ट

भारतीय परिवारों के व्यवहार के पैटर्न में घरेलू खर्चों को लेकर आए बदलावों को इंगित करती एनएसओ की रिपोर्ट पर नीति आयोग के सीईओ की टिप्पणी कि देश में गरीबी का स्तर पांच फीसदी से भी कम हो गया है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है, लेकिन चुनौतियां अब भी बाकी हैं।

खर्च का हिसाब

भारतीय परिवारों के व्यवहार में घरेलू खर्चों को लेकर पिछले दस वर्षों में आए बदलावों को इंगित करती राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की रिपोर्ट जितनी महत्वपूर्ण है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम की इस पर टिप्पणी भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। उल्लेखनीय है कि एनएसओ द्वारा करीब ग्यारह वर्षों के अंतराल के बाद जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय परिवारों का घरेलू खर्च पिछले दस वर्षों में दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। रिपोर्ट का यह कहना कि न सिर्फ शहरी, बल्कि ग्रामीण परिवार भी अब भोजन से ज्यादा कपड़ों, मोबाइल, टीवी व मनोरंजन के दूसरे साधनों पर खर्च कर रहे हैं, दर्शाता है कि न केवल लोगों की आमदनी बढ़ रही है, बल्कि उनकी जीवन-शैली में भी बदलाव आ रहे हैं। नीति आयोग के पिछले वर्ष जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक ने देश की 11 फीसदी आबादी को बेशक गरीबी रेखा से नीचे बताया था, लेकिन एनएसओ की वर्तमान रिपोर्ट के निष्कर्षों से देश में गरीबी की स्थिति और गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों की कामयाबी का ही पता चलता है, और नीति आयोग की टिप्पणी को इन्हीं अर्थों में देखना चाहिए। एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार, शहरी-ग्रामीण उपभोग के बीच फर्क, जो 2004-05 में अपने उच्चतम स्तर 91 फीसदी पर था, अब 2022-23 में 71 फीसदी पर पहुंच चुका है, निरंतर घटती शहरी-ग्रामीण असमानता को ही इंगित करता है। दरअसल, 2014 में केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन के नेतृत्व में गठित पैनल के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 1,407 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये मासिक व्यय से नीचे के परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। जबकि एनएसओ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, आबादी के सबसे कम व्यय करने वाले नीचे के पांच से दस फीसदी लोगों का व्यय भी इससे कहीं ज्यादा है। जाहिर है कि रंगराजन की गरीबी रेखा की परिभाषा को कसौटी मानें, फिर भी नीति आयोग के

प्रमुख की टिप्पणी ही प्रमाणित होती है। हालांकि रिपोर्ट का यह कहना कि ग्रामीण व शहरी परिवारों में अनाज पर होने वाला खर्च पिछले दो दशक पहले की तुलना में घट गया है, भारतीय थालियों में अनाज की घटती मात्रा को ही दर्शाता है, जो चिंताजनक है। गरीबी के स्तर का पांच फीसदी से कम पर पहुंचना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है, लेकिन खाद्य सुरक्षा संबंधी व्यापक लक्ष्यों को देखते हुए अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

छवियों से ही प्रतीक बनते हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनेक छवियां एक में सम्मिलित होकर प्रतीक में बदल कर अपना प्रभाव सृजित करती हैं। राहुल गांधी की कई छवियां या तो अभी विकास की प्रक्रिया में हैं या जो विकसित हैं, उनका अभी संघनित सम्मिलन नहीं हो पाया है।

भारत में छवियों के अध्ययन का अभी तक कोई सुसंगत शास्त्र विकसित नहीं हो पाया है। इसके लिए शोध प्रविधि एवं इसके प्रभावों के अध्ययन, अंकन एवं मापन का काम सुसंगत ढंग से अभी होना बाकी है। 'छवियां' मात्र छवियां नहीं होती हैं, वे धीरे-धीरे प्रतीकों में रूपांतरित हो हमारे मानस को गहरे प्रभावित करती हैं। इसी प्रक्रिया में वे जन-मन की 'गोलबंदी' का स्वरूप रचती हैं।

भारतीय राजनीति एवं चुनावों के अध्ययन में 'वृत्तांतों' पर बातें तो होती हैं, पर छवियों पर व्यापक चर्चा नहीं होती। लोगों के बयानों के आधार पर 'सेफोलॉजी' चुनावी परिणामों की व्याख्या तो करती रहती है, परंतु इस प्रक्रिया में छवियों के पड़ने वाले प्रभावों का न तो राजनीति-वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, न चुनाव विश्लेषक ज्यादा विचार करते हैं। जबकि मेरा मानना है कि राजनीति में छवियां धीरे-धीरे बनती-बिगड़ती हमारी राजनीतिक कल्पनाशीलता (पॉलिटिकल इमैजिनेशन) को प्रभावित करती हैं। इसी प्रभाव निर्माण की प्रक्रिया में वे किसी नेता, किसी राजनीतिक दल एवं किसी विचार के प्रति मतदाताओं को प्रभावित करती रहती हैं। कई बार छवियां विश्वास या अविश्वास का सृजन कर हमें चुनावी बूथों तक ले जाती हैं। वे हममें मोह रचती हैं एवं अनेक बार मोहभंग भी सृजित करती हैं।

बद्री नारायण
साहित्यकार एवं समाजशास्त्री

मैं पिछले कई वर्षों से राजनीतिक नेताओं की छवियों का राजनीतिक एवं चुनावी गोलबंदी पर पड़ने वाले परिणामों के अध्ययन, चर्चा एवं विमर्श में शामिल रहा हूं। मैं राजनीतिक नेताओं की छवियों के बनने, बिगड़ने, उनमें आने वाले ठहराव एवं गतिकी को समझने की कोशिश करता रहता हूं। पिछले दिनों हमने उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों, जिलों एवं कस्बों के 20 से 30 वर्ष के युवाओं के साथ संवाद किया। ये युवा समाज की विभिन्न जातियों एवं वर्गों से थे। इनमें छात्र, छात्राएं, युवक एवं युवतियां, दोनों ही कोटि से जुड़े लोग थे। इनके साथ हुए संवादों से

जो कुछ निहितार्थ निकले, वे बहुत रोचक एवं समकालीन राजनीति को समझने में सहायक हो सकते हैं। इन संवादों से यह समझ में आया कि नेताओं की छवियां मंथर गति से बढ़ती या घटती हैं। इनमें अचानक उछाल या गिरावट उनके द्वारा किए गए बड़े कार्यों या घटनाओं से आती है। मैंने इन संवादों के केंद्र में मूलतः दो छवियों-भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रखा था।

प्रधानमंत्री मोदी की छवियों के वृत्तांतों में उन्हें प्रायः ईमानदार, लोभ-लालच एवं परिवारवाद से मुक्त एवं विकास के लिए समर्पित नेता बताने की प्रवृत्ति दिखी। कई युवा उन्हें देश एवं धर्म के प्रति समर्पित नेता मान रहे थे। यह जानना सबसे रोचक था कि उनमें से कई युवा उन्हें 'युग पुरुष' के रूप में भी देखने लगे हैं। उनका कहना था कि वे एक ऐसे नेता हैं, जो एक पूरे युग को रचने एवं प्रभावित करने वाला काम कर रहे हैं। इन युवाओं के मन में उनकी छवियों के जो वृत्तांत मुझे सुनने को मिले, उनसे दो बातें साफ लगीं। एक तो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन छवियों में रामजन्मभूमि प्राण-प्रतिष्ठा के बाद बड़ा उछाल आया है। उन्हें लोग 'युग पुरुष' के रूप में देखने एवं कहने लगे हैं। उनकी 'युग पुरुष' की छवि सामान्य युवाओं के मन में रामजन्मभूमि प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के बाद की उत्पत्ति इसलिए मानी जानी चाहिए कि उसके पहले ऐसा सुनने को नहीं मिलता था। दूसरा, उनकी छवि आज 'राजनीति से परे' (बियॉंड पॉलिटिक्स) अपने में सामाजिक, धार्मिक एवं परिवारपन से जुड़ी छवियां शामिल किए हुए है।

किसी भी राजनेता की जनछवियों में सकारात्मक एवं नकारात्मक, दोनों ही प्रकार की धारणाएं होती हैं। लेकिन जनता के बयानों में छवियों के संदर्भ में प्रायः सकारात्मक वृत्तांत ज्यादा मिलते हैं। दूसरे, कई बार लोगों में उनके बारे में उदासीनता मिलती है। तीसरे स्तर पर आता है, छवियों की नकारात्मकता का बयान, जिसकी मात्रा या प्रतिशत प्रायः कम ही होता है।

राष्ट्रीय नेताओं में 'अन्य छवि' जनता के मन में जिस नेता की बनती-बिगड़ती रहती है-वह हैं कांग्रेस के राहुल गांधी। राहुल गांधी अपने अनेक प्रतिरोधी राजनीतिक प्रयासों से अपनी छवि विकसित करते रहते हैं। उनकी छवियां अभी विकसित होने के क्रम में हैं। वे छवियां अभी प्रतीक में नहीं बदल पाई हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी की छवियों के साथ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनेक छवियां एक में सम्मिलित होकर प्रतीक में बदल कर अपना प्रभाव सृजित करती हैं। राहुल गांधी की कई छवियां या तो अभी विकास की प्रक्रिया में हैं या जो विकसित हैं, उनका अभी संघनित सम्मिलन नहीं हो पाया है।

उनकी विद्यमान छवियों एवं युवाओं के एक वर्ग में-उनसे की जाने वाली अपेक्षाओं में अंतर्विरोध देखने को मिलता है। कई युवा उनके 'एंग्री यंग मैन' की छवि से सहमत नहीं दिखे। उन्हें अपेक्षा है कि उनकी छवि राजीव गांधी जैसी सौम्यता वाली हो। मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त बिल फाड़ने की घटना का जिक्र करते कई युवा मिले। उनकी छवि निर्माण के सलाहकार शायद यह सोचते हों कि भारतीय युवाओं को गुस्सा पसंद होता है। वे ऐसा सोचकर यह समझने में गलती करते हैं कि भारतीय मानस की आकांक्षा समाहार की होती है, टकराव की नहीं। भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष की राजनीति के प्रतीकात्मक नेतृत्व के रूप में राहुल गांधी की छवियों का विकास एवं विस्तार तो हुआ है, किंतु उन बहुल छवियों को एकीकृत हो एक राजनीतिक प्रतीक में बदलना अभी शेष है। जब तक छवियां प्रतीक में नहीं बदलतीं, वे दीर्घकालिक प्रभाव नहीं छोड़तीं। उनका प्रभाव क्षणिक होता है।

आज राजनीतिक नेताओं की छवियों में परिवर्तन की गति तेज है। इसका प्रमुख कारण है-साइबर स्पेस, मीडिया-वैकल्पिक मीडिया, सोशल साइट्स का विकास एवं विस्तार। भारतीय युवा मानस चूंकि इस 'संचार नेटवर्क' का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, अतः उसके मानस में छवियों के परिवर्तन की गति ज्यादा तीव्र होती है।

राजनीतिक नेताओं की बनती-बिगड़ती छवियां हर बार की तरह इस बार भी भारतीय चुनावों को प्रभावित करेंगी। देखना है, इस बार इनका प्रभाव कैसा होता है एवं किस प्रकार वे चुनाव परिणामों में परिवर्तन ला पाती हैं।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

जग्गी वासुदेव

हम इस धरती पर रहने वाली अब तक की सबसे सुविधा प्राप्त पीढ़ी हैं। मगर दुख की बात यह है कि हम निश्चित रूप से सबसे अधिक आनंदित या सबसे ज्यादा प्रेमपूर्ण या सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण पीढ़ी नहीं हैं।

हर मुश्किल का हल आपके भीतर ही है

__आपने__ अब तक अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है, उन सबका बस एक ही मकसद रहा है। चाहे आपने कॅरिअर बनाना चाहा, कोई कारोबार शुरू किया, पैसे कमाए या फिर परिवार का भरण-पोषण किया, यह सब आपने इसलिए किया, क्योंकि आप बस एक साधारण-सी चीज चाहते थे-खुशी। पर इस दौरान कहीं न कहीं आपका जीवन जटिल हो गया। अगर आप इस धरती पर किसी दूसरे जीव के रूप में पैदा हुए होते, तो सब कुछ बहुत आसान हुआ होता। आपकी जरूरतें सिर्फ शारीरिक होतीं। जिस दिन पेट भर खाना मिल जाता, वह दिन शानदार हो जाता। अपने कुत्ते या बिल्ली पर गौर कीजिए-जैसे ही उनका पेट भर जाता है, वे शांत हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आते हैं, तो स्थितियां बदल जाती हैं। खाली पेट की सिर्फ एक समस्या है। लेकिन जब पेट भरा हो, तो सैकड़ों समस्याएं! जब उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल का सवाल आता है, तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन जैसे ही इसका मसला हल हो जाता है, तो इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। एक इंसान का जीवन गुजर-बसर पर ही खत्म नहीं होता, बल्कि उत्तरजीविता के साथ उसकी जिंदगी शुरू होती है।

आज की पीढ़ी के लिए उत्तरजीविता की प्रक्रिया पिछले किसी भी समय से अधिक व्यवस्थित है। आप एक सुपरमार्केट में जाकर साल भर के लिए अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीद सकते हैं। आप घर से निकले बगैर भी यह काम कर सकते हैं। मानव-इतिहास में ऐसा इससे पहले कभी संभव नहीं था। सौ साल पहले जो चीजें राजा-महाराजाओं को भी मयस्सर नहीं थीं, आज आम आदमी की पहुंच में हैं। हम इस धरती पर रहने वाली अब तक की सबसे सुविधा प्राप्त पीढ़ी हैं। मगर दुखद है कि हम निश्चित रूप से सबसे अधिक आनंदित या सबसे ज्यादा प्रेमपूर्ण या सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण पीढ़ी नहीं हैं। ऐसा क्यों है? हमने बाहर के वातावरण को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की है। अगर हम इसे और ज्यादा व्यवस्थित करते हैं, तो धरती ही नहीं बचेगी! फिर भी आज हम उतने खुश नहीं हैं, जितने हजार साल पहले हमारे पूर्वज थे। तो क्या यह देखने का सही समय नहीं है कि क्या चीज गलत है? खुशहाली अपने भीतर सुखी होने की गहरी भावना है। अगर आपका शरीर सुखी महसूस करता है, तो हम इसे स्वास्थ्य कहते हैं। अगर यह बहुत सुखी हो जाता है, तो हम इसे हर्ष कहते हैं। अगर यह उससे भी सुखी हो जाता है, तो हम इसे प्रसन्नता कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं सुखद हो जाती हैं, तो हम इसे प्रेम कहते हैं। अगर आपकी जीवन-ऊर्जाएं सुखद हो जाती हैं, तो हम इसे आनंद कहते हैं। अगर ये बहुत सुखद हो जाती हैं, तो हम इसे परमानंद कहते हैं। आप बस यही खोज रहे हैं-अपने अंदर और बाहर सुखी होना। जब सुख की अवस्था भीतर होती है, तो इसे शांति, आनंद और खुशी कहते हैं।

दिल और दिमाग में तालमेल...

सूत्र

लोग अक्सर कहते हैं कि उनका दिमाग उन्हें एक दिशा में ले जाता है और दिल दूसरी दिशा में। योग में जो बुनियादी तथ्य हम स्थापित करते हैं, वह है: आप व्यक्ति के तौर पर 'एक' इंसान हैं, अकेले संपूर्ण प्राणी। दिमाग और दिल अलग-अलग नहीं हैं; आप 'संपूर्ण एक' हैं। जब आपके आस-पास का माहौल सुखद हो जाता है, तो इसे सफलता का नाम दिया जाता है।

दूसरा पहलू

शेफील्ड शहर में फुटबॉल की शुरुआत तो हुई ही, इसी शहर ने फुटबॉल के खेल को नियमों में भी बांधा।

उपेक्षित है दुनिया को फुटबॉल सिखाने वाला शहर

ब्रिटेन में शेफील्ड शहर के एक विशाल सुपर स्टोर की जिस पार्किंग में एक फूड ट्रक खड़ा है, वह ऐतिहासिक जगह है। शेफील्ड यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट स्कूल के प्राध्यापक डॉ. जॉन विल्सन कहते हैं कि इसी जगह पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल का जन्म हुआ था। पार्किंग को देखते ही वह करीब दो सौ साल पुराने दौर में पहुंच जाते हैं, जब यहां घास थी, पसीने से लथपथ खिलाड़ी थे और उत्साह बढ़ाती भीड़ थी।

रॉरी स्मिथ

1850-60 में इस शहर में फुटबॉल की सैकड़ों टीमें थीं, जो एक-दूसरे के खिलाफ मैच खेलती थीं। दुनिया के सबसे पुराने दो फुटबॉल क्लबों-शेफील्ड एफसी और हैलम एफसी की स्थापना यहीं हुई थी।

जॉन विल्सन का उत्साह स्वाभाविक है। इस्पात और कोयले के लिए प्रसिद्ध ब्रिटेन का यह शहर फुटबॉल का निर्विवाद जन्म स्थान है, जहां फुटबॉल की शुरुआत तो हुई ही, इसी शहर ने फुटबॉल के खेल को नियमों में भी बांधा। इसी शहर को केंद्र बनाकर *द फूल मॉन्टी* जैसी फिल्म बनी। 1850 और 1860 के दौर में इस शहर में फुटबॉल की सैकड़ों टीमें थीं, जो एक-दूसरे के खिलाफ मैच खेलती थीं। दुनिया के सबसे पुराने दो फुटबॉल क्लबों-शेफील्ड एफसी और हैलम एफसी की स्थापना यहीं हुई थी। शेफील्ड का सैंडीगेट 1860 से ही फुटबॉल मैचों की मेजबानी कर रहा है, जो एक रिकॉर्ड है। अनेक शोधार्थियों का कहना है कि फुटबॉल की संस्कृति वाला यह दुनिया का पहला शहर था।

अब कुछ लोगों ने मिलकर एक संस्था की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य शेफील्ड के गौरवशाली इतिहास के बारे में लोगों को जागरूक करना है।

लेकिन मुश्किल यह है कि खुद ब्रिटेन ही शेफील्ड शहर को फुटबॉल के जन्मदाता का श्रेय देने से कतराता है। अनेक ब्रिटिश विश्लेषक मैनचेस्टर को फुटबॉल का घर मानते हैं, क्योंकि यहां प्रीमियर लीग का आयोजन होता है, साथ ही, यहीं फुटबॉल लीग की शुरुआत हुई थी।

दरअसल, शेफील्ड ने खुद कभी फुटबॉल के जन्मदाता शहर का श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। इसीलिए यह स्थिति है। 'हम अगर गंभीर होते, तो आज फुटबॉल की दुनिया में शेफील्ड की इतनी उपेक्षा नहीं होती', यहां के पूर्व सांसद और टोनी ब्लेअर सरकार में खेल मंत्री रहे रिचर्ड कैबोर्न कहते हैं। लेकिन अब इस दिशा में कोशिश होने लगी है। डॉ. विल्सन ने अपने कुछ उत्साही साथियों के साथ मिलकर शेफील्ड होम ऑफ फुटबॉल नाम से एक संस्था की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य शेफील्ड के गौरवशाली इतिहास के बारे में लोगों को जागरूक करना है।

रिचर्ड कैबोर्न कहते हैं कि शेफील्ड को उसका श्रेय मिलना ही चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य इस शहर के पक्ष में हैं।

©The New York Times 2024

आंकड़े

बढ़ते ई-वाहन

वर्ष 2020 से तीन दिसंबर, 2023 तक कुल 28,77,135 ई-वाहन पंजीकृत किए गए हैं। यानी ई-वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

2020	1,24,681
2021	3,31,635
2022	10,25,118
2023	13,95,701

वर्ष 2023 के आंकड़े 03-12-2023 तक के हैं। इनमें तेलंगाना और लक्षद्वीप के आंकड़े नहीं हैं।

स्रोत : Ministry of Commerce and Industry

समय और परिस्थिति को देखते हुए कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए। पूजा-उपासना से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी के प्राण बचाना है।

सबसे महत्वपूर्ण क्या है

अंतर्यात्रा

शिवकुमार गोयल

एक राजा अपने दरबार में आने वाले पंडितों, विद्वानों से प्रायः प्रश्न किया करते थे कि 'संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है?' कोई भगवान को महत्वपूर्ण बताता, तो कोई राजा को। पर इन उत्तरों से राजा को संतुष्टि नहीं मिलती थी।

एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गए। एक हिंसक पशु का पीछा करते-करते वह बहुत दूर जा निकले। भीषण गर्मी के कारण उन्हें प्यास लगी और चक्कर आने लगा। उन्होंने सामने एक आश्रम देखा, जिसमें एक संत समाधि में लीन थे। वहां पहुंचते ही राजा बेहोश होकर गिर पड़े। संत ने उन्हें उठाकर शीतल जल पिलाया। चेतना लौटने पर राजा ने संत से कहा, 'महात्मन, आप तो समाधि में लीन थे। आपने अपनी समाधि क्यों भंग की?'

साधु ने उत्तर दिया, 'राजन, आपके प्राण संकट में थे। ऐसे समय में मेरे लिए ध्यान की अपेक्षा आपकी सहायता करना ज्यादा महत्वपूर्ण था। धर्मशास्त्र हमें शिक्षा देता है कि समय और परिस्थिति को देखते हुए अपने कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए। पूजा-उपासना से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी के प्राण बचाना है। सर्वोपरि कर्तव्य क्या है, इसका निर्णय परिस्थिति को देखकर ही किया जा सकता है।'

राजा की जिज्ञासा का आज प्रत्यक्ष समाधान हो गया। वह साधु के चरणों में नतमस्तक हो उठे।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 2 अप्रैल, 1955

शिक्षा मंत्री पर लगे आरोपों की जांच होगी

जांच की जायगी
पंजाब के मुख्यमन्त्री श्री सच्चर का बयान
चन्डीगढ़, १ अप्रैल। पंजाब के मुख्यमन्त्री लाला भीमसेन सच्चर ने एक बयान में कहा है कि विरोधी दल ने शिक्षामन्त्री लाला जगतनरायन पर जो आरोप लगाये हैं उनकी जांच की जायगी, यदि एक भी आरोप असत्य निकला तो आरोपकर्त्ताओं

पंजाब के मुख्यमंत्री सच्चर ने कहा कि विरोधी दल ने शिक्षा मंत्री लाला जगतनारायण पर जो आरोप लगाए हैं, उनकी जांच की जाएगी। यदि एक भी आरोप असत्य निकला, तो आरोप लगाने वालों को उसके परिणाम भुगतने होंगे।

अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल रहा है

मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद बैंकिंग और आर्थिक क्षेत्र में कई सुधार किए, जिसके चलते अर्थव्यवस्था में आगे भी तीव्र विकास की संभावना है।

सतीश सिंह

अर्थव्यवस्था

वर्ष 1991 से देश में आर्थिक सुधार का शुभारंभ हुआ था, लेकिन इस दिशा में अब तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। 1991 में विदेश व्यापार, कर सुधार, विदेशी निवेश आदि क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अनेक उपाय किए गए, जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद मिली। मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने से पहले, यानी 2013 में वर्तमान मूल्य पर भारत की जीडीपी 18 खरब डॉलर और 2007 में लगभग 10 खरब डॉलर थी। इस तरह, 1947 से ठीक 60 वर्षों बाद भारत की जीडीपी 2007 में 10 खरब डॉलर की हुई। आज रियल जीडीपी के हिसाब से भी भारतीय अर्थव्यवस्था 30 खरब डॉलर की हो गई है। 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जबकि 2019 में, यानी सिर्फ पांच वर्षों के भीतर यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में श्वेत

पत्र के माध्यम से यूपीए सरकार के कार्यकाल की नाकामियों और मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को आम जनता के समक्ष रखते हुए बताया कि 2014 से पहले देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, जिसके कारण अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मोदी सरकार को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। इसके जवाब में कांग्रेस ने ब्लैक पेपर पेश किया, जिसमें मोदी सरकार की नाकामियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि भाजपा लोकतंत्र को समाप्त करने का काम कर रही है और इसके कार्यकाल में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, भारत की जीडीपी वर्तमान मूल्य पर अभी 37.3 खरब डॉलर की है, जबकि आजादी के समय भारत की जीडीपी 227 अरब डॉलर की थी। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद बैंकिंग और आर्थिक क्षेत्र में कई सुधार किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का शुभारंभ, बैंकों का आपस में विलय, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम-स्वनिधि योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी) आदि का आगाज।

द इंडियन इकनॉमी : ए रिव्यू रिपोर्ट में मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के सफर को आर्थिक सुधारों के संदर्भ में बहुत ही अहम बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 में नॉमिनल जीडीपी के सात प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी के 7.3 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ने का अनुमान जताया गया है। यही नहीं, यह संभावना भी जताई गई है कि भारत की जीडीपी 2030 तक सात प्रतिशत की दर से आगे बढ़ सकती है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल ने भी भारत के वित्तीय क्षेत्र में आई मजबूती और सरकार द्वारा किए गए हालिया संरचनात्मक सुधारों की वजह से सरकार के इस दावे की पुष्टि की है। ऐसे में, 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 50 खरब डॉलर और 2030 में 70 खरब डॉलर से भी अधिक का हो जाएगा। पीपीपी के मामले में 2023 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जबकि चीन और अमेरिका क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर थे।

अस्सी के दशक में पहली बार, वित्त वर्ष 1989-90 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) सूचकांक ने 1,000 के अंक के स्तर को पार किया था। वर्ष 2006 में बीएसई सूचकांक ने 10,000 अंक के स्तर को पार किया। फिर वित्त वर्ष 2014-15 में यह 30,000 अंक के स्तर को और वित्त वर्ष 2018-19 में 40,000 अंक के स्तर को पार किया। वित्त वर्ष 2023 में रिकॉर्ड 70,000 अंक के स्तर को पार कर गया। निफ्टी सूचकांक भी वर्ष 2023 में रिकॉर्ड 21,000 अंक के स्तर को पार कर गया।

भारत में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर नियंत्रण में है। इसके अलावा, प्रति व्यक्ति आय में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आगामी वर्षों में भी मजबूती बनी रहेगी। बेशक जीडीपी के अनुपात में सरकारी कर्ज का प्रतिशत अधिक है, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और अन्य कर व गैर-कर राजस्व संग्रह में आ रही तेजी से इसमें आने वाले वर्षों में कुछ कमी आने की संभावना है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 10

खपत में परिवर्तन

सरकार ने गत सप्ताह घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण के कुछ नतीजे जारी किए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच 2.60 लाख परिवारों में खपत को लेकर एक व्यापक सर्वेक्षण किया। बीते एक दशक में यह पहला ऐसा सर्वेक्षण है जिसके नतीजे सार्वजनिक किए गए हैं। हालांकि 2017-18 में भी ऐसा सर्वेक्षण किया गया था लेकिन आंकड़ों की गुणवत्ता संबंधी समस्या के कारण आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। एक दशक पुराने आंकड़ों के साथ तुलना ने कुछ सुर्खियां बटोरीं। उदाहरण के लिए खाद्य में ग्रामीण परिवारों के व्यय का अनुपात 2011-12 के 53 फीसदी से कम होकर 2022-23 में 46 फीसदी हो गया। इस अनुपात पर सरकार की ओर से बढ़े हुए अनाज आवंटन का सटीक प्रभाव नहीं जाना जा सकता है इसलिए इस आंकड़े से कोई नीति संबंधी निष्कर्ष निकालना असुरक्षित ही माना जाएगा।

इससे भी दिलचस्प यह है कि ग्रामीण परिवारों की खपत के व्यय में 40 फीसदी का इजाफा हुआ और शहरी परिवारों में एक तिहाई। ये ठोस आंकड़े हैं लेकिन यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि खपत में सामान्य वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में नॉमिनल वृद्धि से उल्लेखनीय रूप से कम है। इससे सवाल पैदा होते हैंः क्या भारत सरकारी निवेश या सरकार समर्थित वृद्धि का रुख कर रहा है जबकि पारिवारिक व्ययों में कमी की जा रही है? राष्ट्रीय खातों के मुताबिक प्रति व्यक्ति निजी खपत व्यय, खपत सर्वेक्षणों से निकली राशि से करीब दोगुना है। यह अंतर अस्वाभाविक नहीं है लेकिन इसकी मदद से इस वृहद आर्थिक प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता है कि खपत को अभी भी भारतीय वृद्धि के वाहक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं। सामान्य तौर पर सर्वेक्षण के पिछले संस्करण के आंकड़ों के साथ तुलना करने से बचा जाना चाहिए क्योंकि दोनों सर्वेक्षणों की प्रविधि में काफी अंतर रहा है। पिछले दौर में कम वस्तुओं के व्यय से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे जबकि नए संस्करण में परिवारों के साक्षात्कार के लिए डिजिटल तरीका अपनाया गया और अधिक वस्तुओं पर व्यय को शामिल किया गया।

इस सर्वेक्षण के आंकड़ों की तुलना एक दशक पहले के आंकड़ों से करना शायद समझदारी भरा और आसान न हो किंतु इस दौर के सर्वेक्षण के आंकड़ों का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। उदाहरण के लिए व्यय में असमानता के कुछ परेशान करने वाले परिणाम सामने आए हैं। खपत व्यय के हिसाब से देश की आबादी का निचला पांच प्रतिशत हिस्सा, शीर्ष पांच प्रतिशत हिस्से की तुलना में केवल दसवां भाग व्यय करता है। कुल वितरण में भी असमानता है। खपत व्यय के मामले में राज्यों का भौगोलिक अंतर भी चिह्नित किया गया है। सर्वेक्षण को कोविड के बाद उस समय अंजाम दिया गया जब खपत व्यय में इजाफा हो रहा था। यही वजह है कि कुछ विश्लेषकों ने कहा है कि इन निष्कर्षों को सावधानी के साथ देखना चाहिए। सरकार को इससे यही सबक लेना चाहिए कि इन सर्वेक्षणों को नियमित रूप से अंजाम दिया जाना चाहिए ताकि बेहतर नीति बन सके।

इस प्रकार के सर्वेक्षणों की आवृत्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। खपत के तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं और नीति निर्माताओं को सही निर्णय लेने के लिए तेज और सही आंकड़ों की आवश्यकता है। खपत सर्वेक्षणों का इस्तेमाल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं को नए सिरे से तय करने के लिए भी किया जाता है। अगला उचित कदम होगा इस सूचकांक को उन्नत बनाना ताकि मौद्रिक नीति को बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा खपत रुझान में बदलाव यह बताता है कि खाद्य बास्केट के भीतर भी परिवारों का अनाज पर व्यय कम हो रहा है। खपत बास्केट में बदलाव उत्पादकों के लिए एक संकेत है। गारंटी वाला समर्थन मूल्य मांगने के बजाय किसानों को उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां उपभोक्ता व्यय बढ़ रहा है।

मजबूत विकास के लिए संघवाद जरूरी

सशक्त आर्थिक विकास और उच्च राजनीतिक सद्भाव के लिए विकास के नियोजन में संघवाद को बनाए रखना अनिवार्य है। इस संबंध में बता रहे हैं नितिन देसाई

हर बड़े और विविधतापूर्ण देश में संघवाद राजनीतिक स्थिरता ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी मायने रखता है। भारत जैसे विविधता वाले देश में अपेक्षित विकास नीतियां और कार्यक्रम बनाने के लिए प्रांतीय और उप प्रांतीय स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण में स्थानीय दशाओं का ध्यान रखना होगा और यह केंद्र के विकास लक्ष्य और तरीकों से ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता है।

पिछले तीन दशकों में चीन का तेज विकास एक उदाहरण है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री रॉनल्ड कोस और उनके सहयोगी निंग वांग ने करीब एक दशक पहले लिखे एक शोध पत्र में यह तर्क दिया था कि इस तरह वृद्धि में तेज रफ्तार की व्याख्या विकास के मामलों में केंद्रीय सत्ता के कमजोर या हल्का होने के जरिये की जा सकती है। उनके मुताबिक चीन में विकेंद्रीकरण का उभार बाद में हुआ, 1962 के बाद जब चीन के प्रांत, नगर पालिकाओं, काउंटियों और यहां तक कि छोटे शहरों ने निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रणनीति बनाने के लिए खुली स्पर्धा की।

इसमें कहा गया है, 'चीन एक विशाल प्रयोगशाला बन गया था, जहां कई अलग-अलग तरह के आर्थिक प्रयोग एक साथ करने की कोशिश की गई। दूसरे दशक में क्षेत्रीय स्पर्धा मुख्य परिवर्तनकारी ताकत बन गई, जिसने चीन को सदी के अंत तक एक बाजार अर्थव्यवस्था में बदल दिया।' चीन में विकेंद्रीकरण की नीति की इस शानदार सफलता से एक अहम सबक मिलता है कि भारत में भी हमें इस पर विचार करना चाहिए जहां कि पिछले सात दशकों से भी ज्यादा समय से विकास के नियोजन और कार्यक्रम पर केंद्र सरकार का सख्त नियंत्रण रहा है। लेकिन चीन एक अधिनायकवादी देश है और वहां सभी प्रांतों, उप प्रांतों और शहरों में एक ही राजनीतिक दल का शासन है। विकेंद्रीकरण का जो सकारात्मक पक्ष है वह पूरी तरह आर्थिक ही है।

दूसरी तरफ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं। इसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि किसी राज्य में अगर केंद्र में सत्तारूढ़ दल के विरोधी पार्टी की सरकार है तो उसे भेदभाव का सामना करना पड़े। हाल में कर्नाटक की शिकायत इसका एक उदाहरण है। ज्यादा गंभीर उदाहरण हाल में वह चर्चित आरोप रहा जिसमें कहा गया कि वृहन्मुंबई महानगरपालिका विकास कार्यों के लिए फंड के आवंटन में सत्तारूढ़ दल के विधायकों के प्रति जबरदस्त पक्षपात दिखा रही है। इसलिए, भारत में विकेंद्रीकरण का मामला न केवल बेहतर विकास प्रदर्शन के वादे पर टिका हुआ है, बल्कि अधिक सौहार्दपूर्ण राजनीति की संभावना पर भी निर्भर है।

भारत में विकेंद्रीकरण को अंतर-राज्यीय प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देने वाला नहीं बल्कि उनके बीच व्यापारिक बाधाएं खत्म करने वाला होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि हम 1992 के बड़े उदारीकरण कदम के बाद एक एकीकृत बाजार अर्थव्यवस्था, भौतिक बुनियादी ढांचे के पर्याप्त विकास और संचार, इंटरनेट मार्केटिंग तथा यूपीआई आधारित भुगतान के लिए तीव्र डिजिटल सुविधाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की तरफ कदम बढ़ाने का महत्त्वपूर्ण उदाहरण वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली का लागू होना है।

राज्य स्तरीय विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए दो क्षेत्रों में नीतिगत समायोजन करना होगा। पहला, अपनी दशाओं के मुताबिक उपयुक्त विकास रणनीति तैयार करने के लिए राज्यों को ज्यादा लचीलापन दिखाना होगा। दूसरा, राजकोषीय प्रणाली इस तरह की रखनी होगी कि राज्यों को बिना रोकटोक ज्यादा संसाधन और पूंजी बाजार तक पहुंच हासिल हो।

विकास की रणनीति तैयार करने में लचीलेपन की जरूरत इसलिए ज्यादा है कि भूमि, जल, खनिज संसाधन, जलवायु दशाओं, संख्या, आयु-संरचना और कौशल के लिहाज से मानव संसाधन, उद्यमिता क्षमता और अन्य कई मामलों में अलग-अलग राज्यों में काफी अंतर है। इस बात की निश्चित रूप से आशंका रहती है कि बेहतर संसाधन संपन्न राज्य तेजी से प्रगति करेगा, एक ऐसा जोखिम जो अभी भी विकास रणनीति पर मजबूत केंद्रीय नियंत्रण के दौर में स्पष्ट दिखता है। विकास रणनीति के विकेंद्रीकरण से राज्यों के बीच गहरी होती इस खाई को कम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें इस मामले में ज्यादा अंतर की गुंजाइश देनी होगी कि किन फसलों को प्रोत्साहित करना है, किस तरह की कृषि मार्केटिंग को प्रोत्साहित करना है, किस तरह के औद्योगिक निवेश लाने की कोशिश या आकर्षित करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य के किस क्षेत्र में सरकारी मदद को प्राथमिकता देनी है आदि।

विकेंद्रीकरण के साथ ही केंद्र सरकार की विकास रणनीति तैयार करने में भूमिका बदल जाएगी, और उसे अंतर-राज्यीय सुविधाओं खासकर भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे, विदेश व्यापार नीति संबंधी विचार-विमर्श और राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था से गहराई से जुड़े विकास संबंधी मसलों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा।

तो राष्ट्रीय स्तर के चुनावों में किसी राजनीतिक दल का हिस्सा लेना इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उक्त मसलों पर उसकी क्षमता और प्रभावशीलता कितनी है, बजाय इसके कि वह किसानों, गरीब परिवारों आदि को खैरात के रूप में कितनी रकम देने को तैयार है।

विकास के प्रबंधन का विकेंद्रीकरण प्रभावी हो, इसके लिए हमें राजकोषीय ढांचे को नए सिरे से डिजाइन करने की जरूरत है, ताकि सार्वजनिक कोष ज्यादा स्पष्ट तरीके से उस प्रशासन के हाथों में पहुंचे जो विकास की नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

वर्ष 2022-23 में राज्यों ने समेकित सरकारी व्यय का करीब 55 फीसदी हिस्सा हासिल किया, जबकि उन्होंने समेकित सरकारी कर राजस्व का सिर्फ 38 फीसदी ही जुटाया और सरकार की बाजार से उधारी में उनका हिस्सा 31 फीसदी था। पिछले वित्त आयोग ने यह तय किया था कि केंद्र सरकार के साझा करने योग्य करों का 41 फीसदी हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि 2022-23 में केंद्र सरकार के संग्रहित करों में से राज्यों को सिर्फ 30 फीसदी हिस्सा ही मिल पाया क्योंकि केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष संग्रह का बड़ा हिस्सा विशिष्ट उद्देश्य के उपकरों और अधिभारों से आए, जिनको कि राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता।

राज्यों तक विकेंद्रीकरण ही पर्याप्त नहीं होगा। विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन निर्भर करता है शासन के तीसरे स्तर यानी नगर पालिकाओं और पंचायतों की भूमिका पर। इस तीसरे स्तर के जरिये विकेंद्रीकरण संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में निहित है। लेकिन वास्तव में राजकोषीय संसाधनों की साझेदारी में उनको शामिल करना, उच्च सरकारी स्तर से विवेकाधीन अनुदान प्रदान करने से ज्यादा नहीं हो पाया है। इन तीसरे स्तर की संस्थाओं को राजकोषीय संसाधनों तक बेहतर पहुंच देनी होगी और रोजगार को आकर्षित करने जैसे स्थानीय प्रबंधन एवं विकास की रणनीति तैयार करने में उनको ज्यादा लचीलापन मुहैया कराना होगा।

विकास के विकेंद्रीकरण के लिए आवश्यक है कि केंद्र सरकार उन क्षेत्रों के लिए कार्यक्रमों और नीतिगत समर्थन पर प्राथमिकताओं और रणनीतियों में भिन्नता को स्वीकार करे जो राज्यों की संवैधानिक क्षमता के भीतर हैं। उसे अपने साझा करने योग्य कर संग्रह से परे जाने की कोशिश भी कम से कम करनी चाहिए। दूसरी तरफ, राज्यों को भी विकास के प्रारूप बनाने में उसी तरह का लचीलापन दिखाना चाहिए और पंचायतों तथा नगर पालिकाओं तक राजकोषीय संसाधनों में निर्धारित हिस्सेदारी के समान सिद्धांत को लागू करना चाहिए। विकास की सत्ता का विकेंद्रीकरण राज्यों, नगर पालिकाओं और पंचायतों को उन करों की उगाही के मामले में ज्यादा आक्रामक होने के लिए प्रेरित करेगा जो उनके नियंत्रण में हैं। विकास के नियोजन और राजकोषीय प्रणाली में संघवाद दोनों लिहाज से जरूरी है, ज्यादा सशक्त विकास को बनाए रखने और राज्यों के संघ यानी भारत में ऊंचे दर्जे के राजनीतिक सद्भाव को सुनिश्चित करने के लिए।

विकास योजना और राजकोषीय प्रणाली में संघवाद अधिक सशक्त विकास बनाए रखने और राज्यों के संघ अर्थात् भारत में उच्च स्तर का राजनीतिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

शहरीकरण का जमशेदपुर मॉडल

झारखंड का जमशेदपुर शहर भारत के सफल औद्योगिक प्रयोग और शहरी योजना का साक्षी रहा है। वर्ष 1907 में दूरदर्शी उद्योगपति जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने जमशेदपुर की स्थापना की थी जिसे टाटानगर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के इस पहले योजनाबद्ध औद्योगिक शहर की स्थापना एक सपने के साथ शुरू हुई थी। भारत के अन्य शहरों में हुए अचानक और अनियोजित शहरी विस्तार के विपरीत, जमशेदपुर की शुरुआत ही टिकाऊ विकास और सामुदायिक कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित थी। इस शहर के विकास के तार हमेशा टाटा समूह से जुड़े रहे, जिसकी शुरुआत एशिया की पहली एकीकृत इस्पात कंपनी, टाटा स्टील की स्थापना के साथ हुई थी।

औद्योगिक उद्यम की वजह से इसके आसपास, शहर निर्माण की आवश्यकता अनिवार्य हो गई ताकि उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को इन जगहों पर बसाया जा सके। इस शहर में चौड़ी सड़कें बनाईं गईं और यहां हरियाली से भरे पर्याप्त क्षेत्र रखे गए और कार्यस्थल के पास ही आवासीय क्षेत्र बनाने का खाका भी तैयार किया गया जिनकी वकालत आज के आधुनिक शहरी योजनाकार करते हैं।

इस्पात उद्योग से लेकर विनिर्माण, सेवा और आईटी जैसे विविध क्षेत्रों में विस्तार के जरिये जमशेदपुर ने लगातार खुद को नया रूप दिया है। समूह की ऐसी अनुकूलन क्षमता, भारत के लगातार बदलते आर्थिक परिदृश्य में इसकी निरंतर वृद्धि और प्रासंगिकता के लिए महत्त्वपूर्ण रही है।

हालांकि सुनियोजित योजना के बावजूद, जमशेदपुर शहरीकरण की चुनौतियों से अछूता नहीं रहा है। औद्योगीकरण की रफ्तार बढ़ने के साथ ही प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन और जल की कमी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। टाटा स्टील और अन्य उद्योगों ने उत्सर्जन कम करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए जल संचयन और पुनर्चक्रण जैसी पहलों में निवेश किया है।

जमशेदपुर में शहरी विकास का प्रबंधन भी बड़ी चुनौती रही है। शहर की आबादी लगातार बढ़ने से इसके बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। इसी वजह से नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन करने के मकसद से टाटा का एक उद्यम, जमशेदपुर यूटिलिटीज ऐंड सर्विसेज कंपनी (जेयूएससीओ) स्थापित की गई थी।

अमित कपूर और विवेक देवरॉय

टाटा इस शहर से काफी जुड़ाव महसूस करते थे और इसका नाम भी उनके नाम पर ही था लेकिन इसके बावजूद, कुछ लोगों ने नगर निकाय के मामलों में टाटा की बढ़ती उपस्थिति का विरोध किया क्योंकि कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर होता था जहां इसके कर्मचारी रहते थे और अन्य क्षेत्र नजरअंदाज हो जाया करते थे।

इस मुद्दे को लेकर वर्ष 2018 में टाटा समूह के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। लोगों ने मांग की थी कि स्थानीय निकायों का गठन किया जाए जो शहर के 'निजी' स्थानों के बजाय यहां की जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस क्षेत्र में समान रूप से विकास हो।

हालांकि झारखंड की सरकार टाटा द्वारा पूरे क्षेत्र के विकास के लिए किए गए कामकाज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वहीं कंपनी भी इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसका सबसे अच्छा तरीका यह था कि जमशेदपुर को भारतीय संविधान के विशेष प्रावधानों के अनुसार एक औद्योगिक टाउनशिप में बदल दिया जाए। इसके तहत टाटा स्टील, स्थानीय सरकार और निवासियों के प्रतिनिधियों वाली एक नगर परिषद का निर्माण किया जाना शामिल होगा। यह मॉडल पहले के औद्योगिक टाउनशिपों से काफी अलग होगा, जहां स्थानीय भागीदारी या प्रतिनिधित्व नगण्य होता था जैसा कि राउरकेला और सेलम में देखा गया था।

औद्योगिक टाउनशिप को विशेष आर्थिक क्षेत्रों के रूप में मान्यता मिलती है जो कारखाने लगाने के लिए निजी कंपनियों को रियायतें और अन्य प्रोत्साहन देते हैं। इसका उद्देश्य व्यावसायिक संचालन को सुगम बनाना है।

जमशेदपुर के घटनाक्रम ने शहरी शासन में निजी क्षेत्र की भागीदारी और लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बहस छेड़ दी है। वैसे तो 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी क्षेत्र के स्थानीय सरकारों के लिए शक्ति का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करता है, लेकिन शक्ति के हस्तांतरण का अभाव, भ्रष्टाचार के मामले और स्थानीय निकायों के पास अपर्याप्त संसाधन इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये निकाय अक्सर प्रभावी नहीं होते हैं। ऐसे में, निजी क्षेत्र के हस्तक्षेप को सक्षम प्रबंधन और प्रभावी शासन के अवसर के रूप में देखा जाता है।

शहरी शासन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अक्सर सार्वजनिक क्षेत्र में दक्षता, नवाचार और निवेश लाने के लिए सराहा जाता है। जमशेदपुर में, टाटा समूह के जेयूएससीओ के माध्यम से शहरी प्रबंधन की क्षमता की मिसाल जल आपूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन से लेकर सड़कों पर रोशनी के इंतजाम के साथ-साथ सड़कों के रखरखाव की उच्च-गुणवत्ता वाली सेवाओं में दिखती है। इन मॉडल से अंदाजा मिलता है कि निजी क्षेत्र, हितधारकों के प्रति प्रबंधकीय दक्षता और जवाबदेही से प्रेरित होकर, भारत के कई शहरों के नगरपालिका शासन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को हल कर सकते हैं जैसे कि इसमें कई तरह की अक्षमताएं, परियोजना में देरी और शहरी बुनियादी ढांचे का खराब रख-रखाव शामिल है।

हालांकि चुनौती की स्थिति तब बनती हैं जब निजी इकाइयां अपनी सक्षमता और विशेषज्ञता के बावजूद ऐसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करती हैं जो सार्वजनिक कल्याण के लिहाज से अहम होते हैं लेकिन वे सीधे तौर पर आम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती हैं जिस तरह कोई निर्वाचित संस्था होती है।

आलोचकों का तर्क है कि इस तरह के हालात के परिणामस्वरूप एक ऐसा प्रशासनिक मॉडल तैयार हो सकता है जहां सामुदायिक कल्याण को प्रभावित करने वाले निर्णय, कंपनियां पर्दे के पीछे से करती हैं जिससे संभावित रूप से कमजोर हितधारकों की आवाज और उनकी जरूरतों की बात हाशिये पर चली जाती है। ऐसे में निजी क्षेत्र की क्षमता के फायदे को लोकतांत्रिक शासन की आवश्यकता के साथ जोड़ने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी के लिए व्यापक ढांचा तैयार करना महत्त्वपूर्ण है।

शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज की जगह लेने के बजाय निजी क्षेत्र के कारकों की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, और सीमाओं को परिभाषित करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक निगरानी से जुड़ी प्रणाली मसलन नागरिक परामर्श बोर्ड, सार्वजनिक ऑडिट और फीडबैक तथा शिकायतें दर्ज करने के लिए खुले मंच की व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि निजी निकाय सार्वजनिक कल्याण और जवाबदेही को प्राथमिकता देंगे।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करने के लिए साझेदारी वाला मॉडल बनाना महत्त्वपूर्ण है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और दक्षता का इस्तेमाल निर्वाचित निकायों के अधिकार और जवाबदेही से समझौता किए बगैर किया जाता है।

(कपूर इंस्टीट्यूट फॉर कंपिटिटिवनेस इंडिया के अध्यक्ष और स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसएटीएमसी के लेक्चरर हैं। देवरॉय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं। लेख में जेसिका दुग्गल का भी योगदान)

आपका पक्ष

युवा आबादी के कौशल का समुचित उपयोग करे भारत

सर्वाधिक युवा आबादी वाले देश भारत में स्टार्टअप के लिए जरूरी है कि सरकार की नीतियां सहज-सरल हों और छात्रों की भरपूर मददगार हों। विदेश में जाकर काम करने वाले होनहार भारतीय छात्र जब बड़ी विदेशी कंपनियों के प्रमुख बनकर उस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं तो युवा अपने देश में भी ऐसी कंपनी शुरू कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें मौका मिले। हमें देश को युवाओं की मेधा का फायदा उठाना होगा। अकादमिक, तकनीक और व्यापार क्षेत्र में युवाओं की प्रतिभा को और निखारने की आवश्यकता है। जिस संस्थान में युवाओं को पढ़ाई करने का मौका मिले, उसी संस्थान में ऐसी शुरुआत हो कि युवाओं को नई दिशा मिल सके। वर्तमान में कौशल विकास के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वे प्रभावी नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं। कौशल विकास के मामले में अभी हम बहुत पीछे हैं। युवाओं को कौशल से लैस करने

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित लेडी हॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज के 107वें दीक्षांत समारोह में छात्राओं को उपाधि प्रदान की

के साथ ही इसकी भी आवश्यकता है कि वे अनुशासित बनें और उन संस्कार से लैस हों जिसके लिए भारत दुनिया भर में जाना जाता है। अनुशासन और संस्कारों के बिना इतनी बड़ी आबादी का सही उपयोग नहीं किया जा सकता है। हमारा अनुशासन और संस्कार क्यों बिगड़ रहा है, इस पर गौर करने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के युवाओं को आगे आकर केंद्र और राज्यों की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर, अपने कौशल को विकसित कर देश के विकास में अपना योगदान बढ़ाना चाहिए ताकि भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाया जा सके।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

चुनाव में काले धन पर रोक के लिए सख्त नियम जरूरी

न्यायपालिका ने चुनावी बॉन्ड पर प्रतिबंध लगाया तो राजनीतिक दल नए रास्ते खोज निकालेंगे। काला धन का प्रवाह रोकने के लिए चुनाव आयोग को उम्मीदवारों के लिए कुछ ऐसे सख्त नियम बनाने होंगे जिससे कि चाह कर भी कोई दल काले धन का प्रयोग न कर पाए। इसमें जनता को भी भागीदारी करनी होगी। जब मतदाता बेईमान उम्मीदवारों को नकारने लगेंगे तो राजनीतिक दलों को मजबूरन ईमानदार उम्मीदवारों को खड़ा करना पड़ेगा। इससे बाहुबलियों तथा धनबलियों का प्रभाव धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़े

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए पेट्रोल पंप की संख्या से अधिक चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। देश में वायु प्रदूषण कम करने के प्रयास के तहत ईवी के अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने अगले कुछ वर्षों में पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों को बंद कर पूरी तरह ईवी लाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग की है। अगर लोगों को जगह-जगह चार्जिंग की सुविधा मिले तो ईवी अपनाने में अधिक वक्त नहीं लगेगा। पेट्रोल-डीजल वाहन बंद होने से प्रदूषण भी कम होगा।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज सोमवार को पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं, उन्हें पंजाब प्रांत के लिए इस पद पर निर्वाचित किया गया है। पीएमएल-एन की 50 वर्षीया वरिष्ठ उपाध्यक्ष मरियम ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' (पीटीआई)-समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहिर्गमन के बीच मुख्यमंत्री पद का चुनाव जीता।

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 27 फरवरी 2024

BSP का भविष्य

BSP सांसद रितेश पांडेय ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा देकर BJP में शामिल होने की घोषणा की। बड़ी बात यह है कि वह अकेले नहीं हैं। पार्टी के कई सांसदों के बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी निष्ठा बदल चुकी है। हालांकि जब तक औपचारिक घोषणा न हो जाए तब तक ऐसी अटकलों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। मगर BSP चीफ मायावती ने यह कहकर इन खबरों को कुछ हद तक प्रामाणिकता दे दी है कि अपना हित साधने में लगे ऐसे सांसदों को पार्टी टिकट दे भी तो क्यों।

क्या चौंका पाएंगी मायावती

गिरता ग्राफ | हाल के चुनावों में BSP का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। इसने पार्टी के भविष्य से जुड़ी चिंताओं को मजबूती दी है। 2014 लोकसभा चुनाव में BSP को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में उसने 10 सीटें जीतीं, लेकिन नतीजे आने के ठीक बाद पार्टी ने गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी। 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले लड़ी और सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल कर पाई। उसका वोट शेयर भी गिरकर 12 फीसदी पर आ गया, जबकि 2014 में एक भी सीट हासिल न करने के बावजूद उसे 19.77 फीसदी वोट मिले थे।

गठबंधन से दूरी | BSP समर्थकों में सबसे ज्यादा चिंता पार्टी नेतृत्व की गठबंधनों से दूरी रखने की घोषणा से है। गौर करने की बात है कि BSP हमेशा किसी न किसी गठबंधन के जरिए ही सत्ता तक पहुंची है। एकमात्र अपवाद 2007 के विधानसभा चुनाव रहे जिसमें पार्टी ने बहुजन हिताय की जगह सर्वजन हिताय को चुनावी मंत्र बनाया था। अपने मुख्य समर्थक वर्ग के साथ ही किसी और तबके को साथ लेकर ही वह चुनावी जीत को साध पाती है। ऐसे में मौजूदा पॉलिसी पार्टी के बाहर ही नहीं, अंदर भी कई तरह के सवाल और संदेह पैदा कर रही है।

उत्तराधिकार का सवाल | BSP चीफ ने औपचारिक तौर पर ऐसी घोषणा भले न की हो, पार्टी में यह साफ कर दिया है कि उनके भतीजे आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। बहुजन समाज के हितों को समर्पित मानी जाने वाली इस पार्टी के समर्थकों के लिए यह कथित परिवारवादी रुझान एक नई चीज है और कहा जा रहा है कि उनके लिए इसे पचाना आसान नहीं होगा।

चुनाव नतीजों का इंतजार | वैसे किसी नेता या राजनीतिक दल का भविष्य एकाध फैसलों या कुछेक चुनाव परिणामों से नहीं तय किया जा सकता। आज भी BSP कुछ राज्यों में दलित समूहों के बीच सबसे प्रभावी उपस्थिति रखती है। यही नहीं, अपने लंबे राजनीतिक करियर में मायावती अपने समर्थकों को ही नहीं, विरोधियों को भी चौंकाती रही हैं। लेकिन इस बार वह ऐसा कुछ कर पाती हैं या नहीं, इसका जवाब पाने के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार करना होगा।

धूप-छांव

Gen-Z बोल दूंगी

प्रणव प्रियदर्शी

अपने से पीछे आ रही पीढ़ियों को देखना कभी दिलचस्प लगता है, कभी आनंददायक होता है और कभी-कभी निराश भी करता है। अपने बचपन की बात करूं तो हम जेनरेशन गैप की बातें सुनते हुए बड़े हुए, जहां युवा पीढ़ी पुरानी को दकियानूस मानती थी और पुरानी उसे गैर-जिम्मेदार करार देती थी। इस तरह का सीधा टकराव अब नहीं दिखाई देता तो उसकी वजह शायद यह भी है कि अब दोनों पीढ़ियों ने मन का गुबार निकालने के नए और अलग-अलग रास्ते तलाश लिए हैं। उन्हें एक-दूसरे को खरी-खोटी सुनाने की न तो खास जरूरत है और न फुरसत। फिर भी कभी-कभार जब साफगोई से संवाद का मौका मिलता है या किसी और तरीके से भी, एक की दूसरे के बारे में राय अनायास ही पता चलती है तो वह चकित कर जाती है।

अपने बाद की पीढ़ी की सोच पर आश्चर्य का पहला अनुभव तब हुआ जब हम लगभग सारे दोस्त नौकरी में आ गए और दसवीं-बारहवीं में पढ़ते दोस्तों के छोटे भाइयों से इंटरएक्शन का मौका मिला। उनका कहना होता था कि तुम लोग फालतू के वैल्यूज में बहुत टाइम वेस्ट करते हो। 'हमें क्या करना चाहिए' में अपनी एनर्जी लगाना बेकार है। सही सवाल यह है कि मुझे क्या करना है, और इसके लिए सिर्फ यह पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। इन बातों से हमें कभी थोड़ी निराशा होती तो कभी ईर्ष्या। आपस में हम बात करते कि आज की पीढ़ी ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा स्पेसिफिक है, हमारी तरह कन्फ्यूज नहीं। उसे मालूम है कि उसे क्या चाहिए।

इससे थोड़ा अलग तरह का अनुभव तब हुआ जब एक दिन करीबी मित्र मंडली की एक सदस्य ऑफिस से लौटीं तो थोड़ी डिप्रेस सी लगीं। पूछने पर बताया- रास्ते में दो बहुत प्यारी सी यंग लड़कियां साथ ही आ रही थीं। एक ने कोई नया ऑफिस जॉइन किया था। वह दूसरे को बता रही थी, 'मेरे नए ऑफिस सब बूढ़े लोग हैं यार, कोई भी यंग नहीं है वहां। सब 27-28 साल से ऊपर के ही हैं।' हमारी दोस्त व्यथित थी कि कम ऑन यार, 27-28 साल के हुए तो क्या, हम बूढ़े नहीं हैं भाई।

कुछ ऐसी ही फीलिंग से गुजरती एक लड़की हाल में मिली जो कथित तौर पर बूढ़ी नहीं हुई है। यानी 27-28 की नहीं, अभी 22-23 के ही एज ग्रुप में है। वह अपनी एक हमउम्र दोस्त के घर उसकी स्कूल में पढ़ती कजिन से मिली। बातचीत के दौरान उस कजिन ने इन दोनों को अपनी एक क्लासमेट का चैट दिखाया जिसमें वह धमकी दे रही थी कि तूने होमवर्क नहीं कराया तो स्कूल में मैं तुझे Gen-Z बोल दूंगी। अब Gen-Z तो इस सदी की शुरुआत में जनमी वही पीढ़ी हुई जो आज 22-23 की उम्र में है। दोनों के चेहरे पर वैसे ही भाव थे कि कमऑन यार, Gen-Z होना इतना भी बूढ़ा होना नहीं है।

बोल वचन

ज़रूरी भी होता है चिरकुट

राहुल पाण्डेय

चिरकुट शब्द संधान में पता चला कि कइयों को यह नई पीढ़ी का शब्द लगता है। वह नई पीढ़ी, जो अपने यहां सत्तर-अस्सी के दशक से अभी तक नए बने रहने की जिद पर कायम है। मगर चिरकुट खासा पुराना शब्द है। जायसी ने इसका प्रयोग अपनी लिखाई में कुछ यूं किया है- काढ़हु कंथा चिरकुट लावा/ पहिरहु राते दगल सुहावा। बात हिंदी के शब्दकोश की करें तो पहले-पहल इसका अर्थ 1936 में संपादित रसाल जी के शब्दकोष में फटे-पुराने कपड़े, चिथड़े या गूदड़ के रूप में मिलता है। मगर चिरकुट जायसी और रसाल साहब से भी पुराना है। यह दो शब्दों के योग से बना है चिर+कुट। हिंदुओं में चिर भगवान विष्णु और शिव को भी कहा जाता है, यानी शाश्वत, अविनाशी। चीर, चिर या चीवर वह कपड़ा भी होता है, जिसे साधु-संन्यासी और बौद्ध भिक्षु पहनते आए हैं। अब बचता है कुट या कूट, जिसका अर्थ होता है है कटा-फटा, तुड़ा-मुड़ा, छल, धूर्तता या बेईमानी करना। चीर और कुट जब मिलते हैं, तब कपड़े की जगह सामने एक ऐसा शख्स आता है, जो कपटी, धूर्त और छलिया होता है, जिसके हृदय में भलाई की भावना नहीं होती। इसलिए कई जगहों पर लोग चिरकुट को गाली भी मानते हैं, खासकर अवध में। चिरकुट कुमाऊंनी, नेपाली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, मराठी, बंगाली और उड़िया में भी है, और सब जगह इसे उतनी बेइज्जती नहीं उठानी पड़ती। बल्कि कई जगहों पर चिरकुट के बगैर काम भी नहीं चल सकता। बिहार की अदालतों में जमीन के रजिस्ट्रेशन की नकल लेने के लिए चिरकुट दाखिल करना होता है। यह चिरकुट कागज पर लिखी एक ऐप्लिकेशन होती है, जिस पर स्टैंप टिकट चिपके होते हैं। कुमाऊं में भी कागज के फटे हुए टुकड़े को चिरकुट कहा जाता है, यानी कोई छोटी सी पर्ची, रसीद या रुक्का। अब इतने सारे चिरकुटों के लिए इंग्लिश में कोई एक शब्द तो मिल नहीं सकता, अलबत्ता चिरकुटई कर रहे शख्स के लिए mean जरूर प्रयोग किया जाता है। तो मान सकते हैं कि जब तक दुनिया में mean person रहेंगे, चिरकुट भी बने रहेंगे।

AI Image
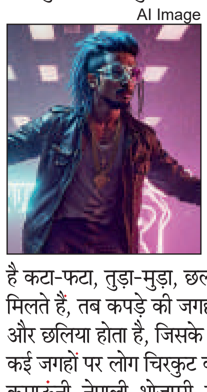

यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बनी सहमति

SP, कांग्रेस के साथ आने से क्या बदलेगा

नदीम

ना-ना करते बात हां-हां में बदल गई। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी (SP) की 17 सीटों के ऑफर को मंजूर कर ही लिया। या यूं कहें कि उसे मंजूर करना ही पड़ा। उसी कांग्रेस को जो पहले यूपी में 2009 लोकसभा चुनाव के नतीजों को आधार बनाते हुए दो दर्जन से कम सीटों पर कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी।

जो मिला, ठीक है | समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले अपने प्रत्याशियों के एलान, फिर 17 सीटें छोड़ने की घोषणा को जो कांग्रेस 'अधिकृत' नहीं मान रही थी, जिसके कई नेता मीडिया में यह स्थापित करने में जुटे थे कि दूसरे विकल्प भी उपलब्ध हैं, उसी पार्टी ने न केवल संख्या में 17 सीटें बल्कि 17 में भी वे सीटें जो समाजवादी पार्टी ने अपने सुविधानुसार दीं, स्वीकार कर लीं। और, अब उसे BJP को हराने की दिशा में उठाया गया बेहद महत्वपूर्ण कदम बता रही है।

कैसे बदला मन | कांग्रेस के मन बदलने की दो बड़ी वजहें हैं। एक यह कि कांग्रेस को जमीनी हकीकत का अंदाजा है। लड़ने को 80 सीटों पर भी लड़ा जा सकता है। 2019 में पार्टी ने यही किया था, लेकिन जीत मिली सिर्फ एक सीट पर। राहुल गांधी भी हार गए थे। दूसरी वजह, कांग्रेस की उम्मीद BSP से जुड़ी हुई थी, लेकिन वह समझौते के लिए तैयार नहीं हुई। वहीं, SP ने 17 सीटें ऑफर कर 'लास्ट एंड फाइनल कॉल' के मोड में आ गई। कांग्रेस को लगा कि अगर यह मौका भी गया तो यूपी में उसका कोई सहारा नहीं होगा।

कैसे हुआ समझौता
- 2019 में कांग्रेस को मिली थी 1 सीट
- सो, 17 सीटों का ऑफर किया मंजूर
- BSP से अलायंस की उम्मीद टूट गई
- SP पर था मुस्लिम वोटरों का दबाव

SP की जरूरत | यूपी में BJP के खिलाफ अगर कोई विकल्प के रूप में जाना जाता है तो वह SP ही है। कांग्रेस तो राज्य में हाशिए पर ही है। BSP की हालत भी कुछ वैसी ही है। 2022 विधानसभा चुनाव में उसका सिर्फ एक प्रत्याशी जीत पाया। 2014 लोकसभा चुनाव में BSP को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2019 में SP से गठबंधन में उसे दस सीटों पर जीत मिली थी। मुख्य विपक्षी दल के नाते SP के लिए जरूरी था कि BJP के खिलाफ एकजुटता हो।

मुस्लिम वोटरों का दबाव | चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल भी SP का साथ छोड़ BJP के संग चला गया। BSP के साथ गठबंधन न करने का एलान पार्टी पहले ही कर चुकी है। ऐसे में उसे लगा कि अगर कांग्रेस के प्रति भी अड़ियल रवैया रहा तो BJP के खिलाफ एकजुटता न हो पाने का ठीकरा उसके सिर ही फूट जाएगा। खास तौर पर मुस्लिम मतदाताओं के बीच इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा, जिसे SP का कोर वोटर समझा जाता है।

17 सीटें ही क्यों | 2019 में कांग्रेस एक सीट जीती और तीन पर वह दूसरे नंबर पर रही थी। SP पहले कांग्रेस को 11 सीटें ही देना चाहती थी। रायबरेली और अमेठी में वह पहले से उम्मीदवार नहीं उतारती है। इस तरह से कांग्रेस की 13 सीटें हो रहीं थी। सात राष्ट्रीय लोकदल के लिए थीं। बची 60 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने लिए रखी थीं। जब राष्ट्रीय लोकदल साथ नहीं रहा तो सात सीटें और बच गईं। इसी वजह से कांग्रेस को 17 सीटें मिल गईं।

2009 का फॉर्म्युला | कांग्रेस हाल-फिलहाल के वर्षों में जब भी किसी दल के साथ गठबंधन के लिए बात करती है तो वह यूपी के 2009 लोकसभा चुनाव को बेस बनाने की जिद करने लग जाती थी। 2024 के लिए भी यही हो रहा था। दरअसल, 90 के दशक से कांग्रेस जब यूपी से बेदखल हुई तो 2009 ही एकमात्र ऐसा लोकसभा चुनाव रहा, जिसमें उसका प्रदर्शन करिश्माई रहा है। उसने तब राज्य में 21 संसदीय सीटें जीती थीं, BSP से भी एक ज्यादा। उस साल SP को 23 सीटों पर जीत मिली थी।

कितना मजबूत गठबंधन | SP और कांग्रेस के बीच समझौता होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस गठबंधन का क्या असर होगा? इसका जवाब है कि BJP के लिए यह चुनौतीपूर्ण साबित हो या ना हो, लेकिन BSP की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। वजह यह है कि मुस्लिम वोटों का रूझान इस गठबंधन के साथ हो सकता है, जिसका नुकसान सीधे तौर पर BSP को होगा। BSP मुस्लिम बाहुल सीटों पर मजबूत मुस्लिम चेहरों के साथ चुनाव में उतरने की योजना बना रही है।

SP का फायदा | यह मानी हुई बात है कि कांग्रेस के पास यूपी में अपना कोई वोट नहीं है। जो कुछ भी है, वह SP का ही है। गठबंधन में भी उसे ही BJP के मुकाबले अपनी ताकत झोंकनी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में वह कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन तब उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन एक बार फिर गठबंधन कर अखिलेश यादव ने यह धारणा बनने से रोका कि कांग्रेस को साथ रखने का प्रयास न करके उन्होंने BJP को मजबूती दी।

2024 कितना अलग | पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में SP और BSP का गठबंधन था, जिसे वोटों के गणित के हिसाब से सबसे मजबूत गठबंधन माना जा रहा था। लेकिन राजनीति में 2+2=4 नहीं होता। अलग-अलग चुनाव लड़ने पर पार्टियों को जो वोट मिल रहे होते हैं, जरूरी नहीं होता कि पार्टियों के साथ आने पर वह भी एक हों। अखिलेश यादव 2019 से सबक लेते हुए इस बार रणनीति तैयार कर रहे हैं।

क्या है रणनीति | अखिलेश यादव ने पार्टी के कोर वोट बैंक के बिखराव रोकने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने प्रत्याशी घोषित करने में भी देरी नहीं की। चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले वह ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर पहुंच कर कोर वोटबैंक के स्थानीय चेहरों की नाराजगी दूर करना चाहते हैं। जिन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा है, उन्हें विधानसभा के चुनाव में समायोजन का वायदा कर रहे हैं।

BSP का रास्ता | BSP का अकेले चुनाव में जाना तय है। कांग्रेस के साथ वह चुनावी गठबंधन से इसलिए बची कि उसके साथ उसे कोई फायदा नहीं दिख रहा था। BSP चीफ मायवती ने कई मौकों पर यह कहा भी है कि चुनाव पूर्व वह किसी गठबंधन में जाने के बजाय चुनाव बाद परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गठबंधन करना पसंद करेंगी।

सेल्फी के चक्कर में सेल्फ रिस्पेक्ट का फालूदा

सर्किट कल रात एक अवॉर्ड फंक्शन में कारपेट ठीक करने के बहाने गया और सेल्फी लेने लगा। फिर उसी सिलेब्रिटी से बोलता है कि आपका नाम क्या है?

नमिता जोशी

आज सर्किट भोत पिट के आएला है। सर्किट तू काइकू ऐसी हरकत करता है कि रोज कोई न कोई तेरेकू धो डालता है? अपुन पूछा तो सर्किट बोला, मुन्ना भाई क्या बताएगा अभी अपुन अपनेइच मुह से। तुम चम्मन चिरकुट से पूछ लो। चिरकुट अपुन के पूछने के पहले ही बोला, भाई इसको सेल्फी मेनिया हो गयेला है। अपुन बोला, उसमे पिटने वाली कौन सी बात? अक्खा इडिया को सेल्फी लेने की बीमारी है। चिरकुट बोला, मुन्ना भाई, पिटने वाले काम तो हैं ही इसके। कल रात एक अवॉर्ड फंक्शन में घुस गया ये। ये पहले कारपेट ठीक करने के बहाने गया और बाद में जल्दी से सेल्फी लेने लगा, वो भी बिना पूछे। उसके बाद उसी सिलेब्रिटी से बोलता है कि आपका नाम क्या है? उसने बोला, क्यों, आपने मेरे साथ सेल्फी तो ले ली, आपको मेरा नाम नहीं पता? तो बोला, अभी ध्यान में नहीं आ रयेला है, जल्दी बताओ अपुन को फेसबुक और इंस्टा स्टोरीज में डालने का है, फिर और भी लोग के साथ सेल्फी लेने का है। सर्किट की ये बात सुनके उस सिलेब ने अपनी सैंडल निकाल के इसके गाल पे छाप दिया।

चिरकुट की ये बात सुनके अपुन कू जितना गुस्सा आया उतनी ही हंसी भी। बिना नाम पूछे सिलेब के साथ सेल्फी लेके इंस्टा पे डालके क्या समझता है तू सर्किट? सर्किट बोला, भाई अपुन की शान बढ़ती है, अपुन के गांव के दोस्त और रिलेटिव समझते कि अपुन मुंबई में फिल्म स्टार्स के बीच खेलता-कूदता है।

AI Image

भेजा फ्राई

अपुन ने समझाया कि सेल्फी के लिए सेल्फ रिसपेक्ट काइकू खोता है रे सर्किट। अपनी इज्जत बनाने के और भी तरीके हैं, वो ढूंढ। फर्स्ट टाइम देखा कि सर्किट अपुन की बात ध्यान से सुन रयेला है। बोला, ठीक है भाई। अपुन बिना सेल्फ रिस्पेक्ट खोए रिस्पेक्ट कमा के दिखाएगा। एक वीक के बाद मिलना बोल के सर्किट उदर से कल्टी हो गया। एक वीक तक सर्किट हंसता-खेलता दिखाई दिया। अपुन कू अहसास हो गया कि इसने रिस्पेक्ट कमाने का सही तरीका ढूंढ लिया। पन अपुन पूछेगा एक वीक के पूरा होने के बाद ही। वीक खल्लास हुआ और अपुन पहुंचा सर्किट की खोली में। पन उसके रोने की आवाज तो पांच खोली दूर से आ रयेली है। लगता है फिर से पिटने का काम किएला है।

काइकू भेजा फ्राई कर रयेला है सर्किट? ये पूछा ही था कि चिरकुट पहले ही बोल पड़ा, मुन्ना भाई इस बार इसने अपनी रिस्पेक्ट का आइस्क्रीम फालूदा बना लिया है। रिस्पेक्ट वाले लाइक्स लेने के चक्कर में पप्पू पेजर ने इसको आइडिया दिया कि वो दुनिया के हर सिलेब्रिटी और फेमस लोगों से मिले बिना ही उनके साथ सेल्फी बना देगा इसकी। बस फिर क्या था, क्या ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और क्या दीपिका पादुकोण, पप्पू पेजर ने सर्किट के फोटो का कट आउट बना कर सबके साथ एक-एक फोटो फोटोशॉप कर दी और रोज फेसबुक पर डालने लगा। सारे रिलेटिव वाह-वाह करने लगे और ये हवा में उड़ने लगा। कल इसने गड़बड़ कर दी कि एक के बाद एक इंडियन हीरो और इंटरनैशनल हीरो के साथ फोटो डाल दी। लोगों को आ गया गुस्सा। रिस्पेक्ट वाले कॉमेंट्स करने वाले दोस्तों ने इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी कि एक ही दिन में चांदनी चौक टु चाइना कैसे पहुंच गया? बोले तो इंडियन हीरो के साथ ताज में फोटो और फिर हॉलिवुड में लियोनार्डो डि कैप्रियो के साथ लॉस ऐंजिलिस कैसे पहुंच गया? काइकू उल्लू बना रयेला है, ऐसे ऐसे कॉमेंट्स डाल रयेले हैं इसके रिलेटिव। सेल्फी ले अपने दोस्तों के साथ, जो तुझे जानते हैं। अनजान लोगों साथ सेल्फी नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रख।

मुंबइया स्टाइल में मुन्ना और सर्किट का ये भेजा फ्राई आपको कैसा लगा? हमें अपनी राय लिखकर भेजिए इस मेल आईडी पर **nbtreader@timesgroup.com** और सब्जेक्ट मे लिखे-**'भेजा फ्राई'**

विशुद्ध राजनीति
पॉलिटॉक

स्टार पर दुविधा

पंजाब की एक लोकसभा सीट के लिए BJP ने कई चेहरों को शॉर्टलिस्ट किया है। एक बॉलिवुड सुपरस्टार से लेकर एक पूर्व स्टार क्रिकेट खिलाड़ी तक के यहां से पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने की चर्चा है। वैसे, अभी उस सीट से BJP के ही सांसद हैं, जो बॉलिवुड के स्टार भी हैं। पार्टी का मानना है कि पंजाब में जिन सीटों पर उसके जीतने की संभावना है, उनमें से एक सीट यह भी है। लेकिन यहां से किसे प्रत्याशी बनाया जाए, इसे लेकर BJP दुविधा में है। अगर किसी स्टार को इस सीट से पार्टी चुनाव में उतारती है तो उसका लाभ और नुकसान दोनों हो सकता है। इसके अपने कारण हैं। असल में, मौजूदा सांसद से स्थानीय लोग नाराज हैं। उसकी वजह यह है कि सांसद महोदय पूरे कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र से करीब-करीब गायब रहे। यही नहीं, वह संसद में भी कभी नहीं दिखे। उनके खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र में तब बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जब वह अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए वहां से 50 किलोमीटर करीब तक गए, लेकिन संसदीय क्षेत्र नहीं पहुंचे। BJP को लग रहा है कि कहीं इस वजह से स्टार प्रत्याशियों से वोटर नाराज न हो जाएं। हालांकि मौजूदा सांसद से पहले भी इस सीट से BJP के जो सांसद थे, वह भी पुराने बॉलिवुड स्टार थे। लेकिन वोटरों के बीच उनकी छवि अच्छी थी। खैर, देखना यह है कि इन सबके बीच पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है।

डिप्लोमैट लड़ेंगे चुनाव!

आगामी लोकसभा चुनाव में एक और पूर्व विदेश सचिव व डिप्लोमैट के BJP से मैदान में उतरने की चर्चा है। हर्षवर्धन श्रृंगला पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, उनका नाम तय हो चुका है। लेकिन उन्हें लेकर अंदरखाने चर्चा यहीं तक सीमित नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आती है तो श्रृंगला को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। वह पीएम नरेंद्र मोदी के पसंदीदा अधिकारियों में शामिल रहे हैं। श्रृंगला को बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चा इसलिए उड़ी है क्योंकि मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर मोदी की अगली सरकार में नहीं रहना चाहते। कहा जा रहा है कि वह उम्र की वजह से पद छोड़ना चाहते हैं। वैसे, विदेश मंत्री का दायित्व संभालने वाले जयशंकर भी पहले विदेश सचिव थे। पिछले दस वर्षों में वह पीएम मोदी के सबसे करीबी लोगों में शामिल रहे हैं। मोदी सरकार की कूटनीतिक और सामरिक नीतियों में उनका अहम योगदान माना जाता है।

नीतीश के इरादे

बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर BJP के साथ सरकार तो बना ली। उन्होंने BJP के दो डेप्युटी सीएम सहित नौ मंत्रियों के साथ शपथ भी ले ली। नीतीश-BJP की सरकार बनते वक्त कहा गया कि बहुत जल्द राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन नीतीश के शपथ लेने के बाद से अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। पहले दावा किया गया था कि 2020 की तर्ज पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। खैर, अब इसमें देरी को लेकर वहां सवाल उठने लगे हैं। इसके साथ अफवाहों का बाजार भी गर्म हो रहा है। जब नीतीश कुमार ने इस बार BJP के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया तो कहा गया कि वह लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव कराने के हक में हैं। नीतीश को लगता है कि इससे लोकसभा की तरह विधानसभा में भी वह BJP से अच्छी सीटें लेने में सफल होंगे और JDU को विधायकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन BJP ने लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने से इनकार कर दिया है। इस बीच, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने की वजह से जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। हालांकि BJP और JDU दोनों यही दावा कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो जाएगा और इसके लिए फॉर्म्युला भी तय हो चुका है।

यादव परिवार की 'हॉट सीट'

यूपी से लोकसभा की 80 सीटों में से पांच पर अखिलेश यादव परिवार से उम्मीदवार होते हैं। इन पांच सीटों में से एक फिरोजाबाद इस बार 'हॉट सीट' बन गई है। यहां से प्रफेसर साहब के बेटे को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। जैसे BJP के चाणक्य अमित शाह माने जाते हैं, वैसे ही समाजवादी पार्टी के भीतर प्रफेसर साहब की हैसियत है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उनके बेटे को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार प्रफेसर साहब ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि फिरोजाबाद को सेफ रखने के लिए प्रफेसर साहब हर मुमकिन कदम उठा सकते हैं। उसी समीकरण के तहत राज्यसभा के लिए रामजी लाल सुमन को टिकट दिया गया है। वह फिरोजाबाद के सांसद भी रह चुके हैं। इलाके में उनका असर भी माना जाता है। सीट यादव परिवार को जाने के बाद उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था। उनकी नाराजगी कहीं भारी न पड़ जाए, इसका खयाल रखते हुए उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया गया। इस क्षेत्र से पूर्व विधायक अजीम भाई भी आते हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काटा तो वह BSP में चले गए थे। उनकी नाराजगी भी दूर करने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी के चीफ ने फिरोजाबाद जाकर उनसे मुलाकात की। चर्चा है कि उनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए उन्हें विधानपरिषद भेजा जा सकता है। यानी यादव परिवार फिरोजाबाद सीट पर जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार है।

राजा का प्रेशर

यूपी में राजा भैया की पॉलिटिक्स हमेशा सत्तारूढ़ दल के साथ चलती है। सिर्फ मायावती ही थीं, जिनके साथ उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। बहनजी जब मुख्यमंत्री थीं, तब उन्होंने राजा भैया को जेल में ही रखा था। इधर, जब से यूपी में BJP की सरकार बनी है, वह उसी के पाले में खड़े नजर आते हैं। BJP को भी उनकी सत्तारूढ़ दल के साथ चलने की आदत का पता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में राजा भैया को बहुत तवज्जो नहीं मिल रही। पार्टी को पता था कि BJP के साथ खड़े होने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन राज्यसभा चुनाव की वजह से राजा भैया का भाव बढ़ गया है। असल में, राज्यसभा के लिए BJP ने यूपी से आठ प्रत्याशी उतारकर रिस्क लिया है। लेकिन इसी से राजा भैया को अपनी अहमियत दिखाने का मौका मिल गया। BJP को अपने आठवें प्रत्याशी को जिताने के लिए बाहर से दो वोट चाहिए। इनमें से एक राजा भैया हो सकते हैं। इन हालात में राजा भैया ने समाजवादी पार्टी से बातचीत शुरू कर दी। वह दिखाना चाहते थे कि राज्यसभा चुनाव में उनका वोट अखिलेश यादव की पार्टी को भी जा सकता है। खैर, इसी बीच, BJP के प्रदेश अध्यक्ष उनके घर पहुंचे और गिले-शिकवे दूर किए। अब खबर आ रही है कि राज्यसभा चुनाव में राजा भैया BJP को ही वोट देंगे।

AI Images

रीडर्स मेल
www.edit.nbt.in

■ गठबंधन के मायने

26 फरवरी का संपादकीय 'गठबंधन की गाड़ी' पढ़ा। 8 महीने से विपक्षी दल महागठबंधन बनाने में जुटे हुए थे। मगर लंबे समय तक वे सीटों के बंटवारे को लेकर सामंजस्य नहीं बना सके। अब कुछ राज्यों में सामंजस्य बना भी है तो बड़ा ही बेढंगा। AAP और SP ने कांग्रेस को दोयम दर्जे की पार्टी बना कर रख दिया है। उधर राहुल गांधी की बेमौसम न्याय यात्रा ने चर्चा के लिए महत्वपूर्ण समय को व्यर्थ ही खर्च कर दिया है। न्याय यात्रा को भी जैसा चाहिए वैसा समर्थन नहीं मिल सका। बस सस्पेंस इतना है कि 400 से कितनी ऊपर या नीचे सीटें NDA गठबंधन प्राप्त करता है।

विभूति बुपक्या, ईमेल से

■ रिश्ता जो टिक पाए

'भेजा फ्राई' कॉलम में 13 फरवरी को प्रकाशित लेख 'रिस्पेक्ट मालूम नहीं, अपुन तो गिफ्ट ही देगा' में बड़े ही दिलचस्प अंदाज में वैलंटाइन डे के ड्रामे को परत-दर-परत उधेड़ा गया है। लेखिका ने कहा है, प्रॉमिस डे पर उसने प्रॉमिस मांगा कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि अक्खा लाइफ मेरे ही रहोगे। दरअसल ऐसा होता नहीं है। हर साल वैलंटाइन डे आते-आते किताबों के पन्नों में रखे फूल की पंखुड़ियों की तरह रिश्ते भी सूखने लगते हैं। फिर प्यार वाला मौसम आता है। नई टहनियों में खिले फूलों की तरह रिश्ते महकते हैं। लेकिन मौसम-दर-मौसम टिकने वाला रिश्ता भी चाहिए।

अरुणिमा श्रीवास्तव, ईमेल से

■ जेलेंस्की पर दबाव

दो साल से यूक्रेन अस्तित्व की लड़ाई से जूझ रहा है। शुरुआती यूक्रेनी प्रतिरोध ने आश्चर्यचकित कर दिया था। जेलेंस्की जिन्हें कभी नायक के रूप में सराहा जाता था, अब उन्हें बातचीत करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कारण कि पश्चिमी सहायता कम हो रही है। पूतिन आंतरिक उपायों और चीनी समर्थन की बदौलत प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। वह पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दे रहे। युद्ध अधर में लटका हुआ है, अमेरिका में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना भी यूक्रेन की उम्मीदों को कम कर रही है।

मोहम्मद तौकीर, ईमेल से

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

पहली पारी में लीड लेकर गरज रहे थे अंग्रेज, अंत में पलटी बाजी - खबर
- बाजीगर पहले पतंग की डोर ढीली छोड़ता है, फिर पेच काट देता है!

सौरभ राणा

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

अंतर्मन ठीक रहेगा तभी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं

बी के शुक्ला

कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। दुनिया की सेवा करने से पहले खुद की और अपने घर-परिवार की खिदमत करनी होती है। क्योंकि समाज से पहले व्यक्ति आता है, जो उसकी इकाई है। पर यह भी सच है कि विश्व कल्याण के कार्य में समर्पित व्यक्ति का कल्याण तो अपने आप हो जाता है। यानी परमार्थ को प्राथमिकता देने वालों की मनोकामना अपने आप सिद्ध हो जाती है।

यह सत्य है कि हमारी आंतरिक अवस्था से बाहरी व्यवस्था बनती और बिगड़ती है। हमारी बाहरी परिस्थिति को ठीक करने के लिए हमें अपनी आंतरिक स्थिति को ठीक करना होता है। मतलब, हम पहले अपनी मन की वृत्ति और दशा को ठीक करें, उसे सही दिशा दें, तो हमारी बाहरी वातावरण और परिवेश की दशा और दिशा ठीक हो जाएगी। मानसिक और बौद्धिक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा अंदर से बाहर की ओर जाता है। अंतर्मन और अंतरात्मा से आने सकारात्मक संकल्प और वृत्ति की शक्ति हमारे आभा मंडल, वायु मंडल, प्रवृत्ति और पर्यावरण को स्वस्थ, स्वच्छ व सुखदायी बनाती है।

इसलिए खुद को आंतरिक रूप से ठीक किए बिना हम न तो अपनी और न दूसरों की अवस्था ठीक कर सकते हैं। पहले हम अपने मनोभाव, सोच और नजरिए को संयमित करें, तभी दूसरों का आदर और सम्मान कर पाएंगे। इसी को कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। अंतरात्मा का पहला घर उसका शरीर है। उसके शरीर को चलाने वाली उसकी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। साथ में मन, बुद्धि और संस्कार भी हैं। यह सब उसके दैहिक घर-परिवार के सदस्य हैं, जिनका उचित भरण-पोषण, लालन-पालन का दायित्व घर की मुखिया अंतरात्मा के ऊपर है। मन, बुद्धि, संस्कार और शरीर रूपी इस घर की देख-रेख के उपरांत ही हम सही अर्थ में दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है, God helps them who help themselves, यानी ईश्वर उनकी मदद करते हैं, जो खुद की मदद करते हैं।

हम दूसरों की मदद के लिए तभी आगे आते हैं, जब उनके प्रति हमारे मन में दया, करुणा और सहानुभूति जागती है। अक्सर निस्वार्थ समाजसेवी व धार्मिक संस्कार वाले लोगों के मन में असहाय और अभावग्रस्त लोगों के लिए दया, करुणा व सहायता का भाव जागता है। देह अभिमान और दुनियावी उपलब्धियों के अहंकार में चूर लोगों में दूसरों के प्रति दया भाव कम जागता है। विकारों से मुक्ति के लिए अंतरात्मा की चेतना को जगाना जरूरी है। इसके बिना आत्मिक शक्तियों की जागृति संभव नहीं है। इसलिए चेतना की जागृति के लिए अध्यात्म यानी आत्म अध्ययन, आत्म चिंतन, आत्म अनुभव करने की और परमात्मा के सत्य स्वरूप और सद्गुणों की स्मृति में रहने की जरूरत है। परमात्म गुण और शक्तियों की मदद से ही मनुष्य अपने मनोविकारों के ऊपर विजय पा सकता है।

देखा जाए तो, किसी को नैतिक और भौतिक अभाव से मुक्त करने के लिए उसको दैहिक भाव से मुक्त कर, आध्यात्मिकता के मौलिक भाव जैसे कि आत्मिक शांति, प्रेम और आनंद के मनोभाव में स्थित कराना होगा। तभी उसका दैहिक, मानसिक और नैतिक अशांति, रोग, कष्ट दूर हो सकता है। इसी से खुशी जैसी खुराक और आत्म संतुष्टि जैसे खजानों के रूप में आशीर्वाद प्राप्त होता है। वही सच्ची कमाई संतोष रूपी श्रेष्ठ धन दौलत है, जो कि संचित प्रारब्ध और उत्कृष्ट कर्म फल के रूप में आत्मा के साथ जाएगा। बाकी सुख-दुख, स्वार्थ सब सब नष्ट हो जाएगा।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

Join Magazine Group @ ₹60/m WhatsApp To 8969469464 Join Epaper Group @ ₹30/m WhatsApp To 8969469464

कल्पमेधा

मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या हैं। इसलिए सबसे पहले मनुष्य के कर्म को देखो।

- जान लाक

खर्च का बोझ

अर्थव्यवस्था के तेज विकास और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के दावों के बीच हकीकत यह है कि पिछले बारह-तेरह सालों में लोगों का घरेलू खर्च बढ़ कर दोगुने से अधिक हो गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के ताजा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के मुताबिक मौजूदा कीमतों पर शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत घरेलू खर्च 2011-12 के 2,630 रुपए से बढ़ कर 2022-23 में दोगुने से अधिक यानी 6,459 रुपए हो गया है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में यह 1,430 रुपए से बढ़कर 3,773 रुपए हो गया है। इसमें यह भी जाहिर हुआ है कि गैर-खाद्य वस्तुओं पर खर्च बढ़ा है, जबकि खाद्यान्न पर खर्च पहले की तुलना में कम हुआ है। फलों, सब्जियों, दूध, मछली, खाद्य तेल आदि पर खर्च बढ़ा है। इसी तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, वस्त्र और दूसरी जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च बढ़ा है। इसकी एक वजह तो यह बताई जा रही है कि कोविड के समय शहरों से गांवों की तरफ लौटे लोगों के कृषि क्षेत्र में समाहित हो जाने से उस क्षेत्र का औसत उपभोग खर्च बढ़ा है। मगर यही तर्क शहरी खर्च बढ़ने पर लागू नहीं होता। यह तब है, जब सरकार लगातार महंगाई पर काबू पाने का प्रयास कर रही है।

इन आंकड़ों के समांतर दावा यह भी है कि गरीबी में पांच फीसद की कमी आई है। बहुआयामी गरीबी से करीब तेईस करोड़ लोगों के बाहर निकलने का आंकड़ा भी कुछ दिनों पहले चर्चा में था। इन सबके बीच एक तथ्य यह भी है कि प्रति व्यक्ति आय में कोई उल्लेखनीय बढ़ोतरी नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक आय भी लगभग उतनी ही है, जितना प्रति व्यक्ति मासिक खर्च है। मगर इससे प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति खर्च का समीकरण संतुलित नहीं होता। ज्यादातर परिवारों में एक ही व्यक्ति कमाने वाला होता है, जबकि उस पर निर्भर औसतन तीन लोग होते हैं। इन्हीं आंकड़ों के बीच सरकार का दावा है कि वह बयासी करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराती है। यानी प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू व्यय के औसत में इस आबादी का हिस्सा भी शामिल है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि यह सर्वेक्षण ग्यारह सालों बाद आया है, इसलिए इसमें प्रति व्यक्ति खर्च ऊंचे स्तर पर नजर आ रहा है।

महंगाई और प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ना एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था की निशानी माना जाता है। मगर इसके साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय में भी समतुल्य बढ़ोतरी दर्ज होना आवश्यक है। विचित्र है कि प्रति व्यक्ति आय उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है, जिस अनुपात में महंगाई और घरेलू खर्च बढ़ रहा है। इसकी बड़ी वजह रोजगार के नए अवसर सृजित न हो पाना और कोविड के दौरान बाहर हुए लोगों का वापस रोजगार में न लौट पाना है। जो लोग कृषि क्षेत्र में समाहित हो गए हैं, उन्हें भी दैनिक मजदूरी उपलब्ध नहीं हो पाती। कृषि क्षेत्र खुद कई संकटों से गुजर रहा है। मौसम की मार से फसलों के बर्बाद होने और लागत के अनुपात में फसलों की वाजिब कीमत न मिल पाने की वजह से इस क्षेत्र में मजदूरी घटी है। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों में भी काम सौ दिन से घट कर मुश्किल से साल में साठ दिन ही मिल पाता है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि घरेलू खर्च बढ़ने से लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

बेखौफ अपराधी

हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या से एक बार फिर यही जाहिर हुआ है कि अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि वे किसी नेता की हत्या करने से भी नहीं हिचक रहे। कई बार घटना की प्रकृति से भी पता चलता है कि हमलावर कानून से कितने बेखौफ हैं। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कार से पीछा करके अपराधियों ने सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें नफे सिंह की जान चली गई और उनके कई सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। घायल हुए एक अन्य कार्यकर्ता को भी नहीं बचाया जा सका। हालांकि इस हत्याकांड की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, मगर अब घटना के बाद एक रस्म की तरह पुलिस ने आरोपियों को जल्दी पकड़ लेने का भरोसा दिया। विडंबना है कि ऐसे आश्वासन अगर पूरे हो भी जाते हैं तो अगली घटनाओं को रोकने के लिए सबक नहीं बन पाते। सवाल है कि ऐसी नौबत आने से पहले सरकार और प्रशासन की ओर से समय पर ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए जाते, जिससे अपराधों पर लगाम लगाई जा सके!

ऐसी घटनाओं में एक आम आशंका यह उभरती है कि क्या इसके पीछे राजनीतिक खींचतान, आपसी रंजिश या फिर महत्त्वाकांक्षाओं का टकराव मुख्य कारण है। यह नफे सिंह राठी की हत्या के संदर्भ में अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, मगर उनके बेटे ने इसके पीछे राजनीतिक साजिश होने का दावा किया और कहा कि ऐसे लोग हैं जो उनके पिता को विधायक के रूप में नहीं देखना चाहते थे। इस मामले में प्रशासनिक तंत्र की कोताही इस रूप में सामने आई है कि खबरों के मुताबिक राठी पर पहले भी हमले हुए थे और लगातार धमकियां दी जा रही थीं। इसके बावजूद सरकार की ओर से उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी। अगर इस अपराध की साजिश पहले रची गई थी, तो प्रशासन इसे भांपने में कैसे नाकाम रहा? यह संभव है कि राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा या आपसी रंजिश के तहत एक नेता की हत्या कर दी गई हो, लेकिन यह साफ है कि अगर सरकार ने समय पर जरूरी कदम उठाए होते, तो इस वारदात को रोका जा सकता था।

भिक्षावृत्ति से मुक्ति का संकल्प

भिक्षावृत्ति एक सामाजिक समस्या है, जिसे हल करने के लिए सरकार के साथ-साथ सामाजिक संस्थाओं तथा भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रयास करना चाहिए।

रंजना मिश्रा

भारत में रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियां भिन्न-भिन्न हैं। कुछ लोगों को अपनी आर्थिक तंगी के कारण भिक्षावृत्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। मगर अब केंद्र सरकार ने भारत को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए एक योजना बनाई है। इसके तहत, भिक्षावृत्ति में लगे लोगों को चरणबद्ध तरीके से पहचानकर उनको समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए पहले ऐसे लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें लोगों की उम्र, लिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और भिक्षावृत्ति में लिप्त होने के कारणों आदि का पता लगाया जाएगा। इन लोगों को पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने से लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। रोजगार के अवसर प्रदान करके लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लोगों को बुढ़ापे, बीमारी और अन्य आपात स्थितियों में आर्थिक सहायता मिलेगी।

भिक्षावृत्ति के पीछे गरीबी, अशिक्षा, मानसिक विकार, बाल शोषण आदि मुख्य कारण हैं। गरीबी भिक्षावृत्ति का सबसे प्रमुख कारण है। दरअसल, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं होते। ऐसे लोग भिक्षावृत्ति को एकमात्र आय का स्रोत बना लेते हैं। इसी तरह अशिक्षित लोगों के पास भी रोजगार के अवसर कम होते हैं। ऐसे लोग भी भिक्षावृत्ति पर निर्भर हो जाते हैं। मानसिक रूप से बीमार लोग समाज में अपना स्थान नहीं बना पाते और भिक्षावृत्ति पर निर्भर हो जाते हैं। बाल शोषण भी भिक्षावृत्ति का एक कारण हो सकता है। दरअसल, जो बच्चे शोषण का शिकार होते हैं, वे भी भिक्षावृत्ति पर निर्भर हो जाते हैं। भिक्षा मांगने वालों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो सिर्फ आलसी होते हैं। ये लोग बीमारी, चोट लगने का या कोई अन्य बहाना बनाकर, अपनी लाचारी दिखाकर भिक्षा मांगते हैं। इनके अलावा कुछ संगठित गिरोह भी हैं, जो पैसों के लालच में गरीबों और लाचारों से जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं।

भारत में भिखारियों की कुल संख्या 4 लाख 13 हजार 670 है, जिनमें पुरुषों की संख्या 2 लाख 21 हजार 673 तथा महिलाओं की संख्या एक लाख 91 हजार 997 है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। भिक्षावृत्ति से निरंतर चोरी, हत्या, लूटपाट जैसे बढ़ते अपराध चिंता का विषय हैं। बाल भिक्षावृत्ति के लिए बच्चों की तस्करी के बढ़ते मामले भी चिंताजनक हैं। भिक्षावृत्ति एक सामाजिक समस्या है, जिसे हल करने के लिए सरकार के साथ-साथ सामाजिक संस्थाओं तथा भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रयास करना चाहिए। सामान्य तौर पर किसी भी देश और राज्य में भिखारियों का होना इस बात का प्रमाण होता है कि वहां की सरकारें अपने सभी नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं का खयाल रखने में सफल नहीं रही हैं। मगर संगठित तौर पर चलने वाले भिक्षावृत्ति तंत्र को मानव तस्करी और अपहरण जैसे अपराधों के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए।

भिक्षावृत्ति मुक्त भारत का लक्ष्य भारत को एक ऐसे देश के रूप में विकसित करना है, जहां कोई भी व्यक्ति भिक्षावृत्ति पर निर्भर न हो। भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार को भिक्षावृत्ति के मूल कारणों को समझना और उन पर प्रभावी तरीके से काम करना होगा। इसके अलावा भिक्षावृत्ति के खिलाफ जन जागरूकता फैलानी होगी। लोगों को भिक्षा देना

भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। इन लोगों को आश्रय, कौशल, शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। दरअसल, भिक्षावृत्ति एक जटिल समस्या है, जिसे हल करने के लिए सरकार को एक समग्र योजना बनानी होगी। लोगों को समझाना होगा कि भिक्षा देने से भिखारी आत्मनिर्भर नहीं बनते, बल्कि उनके जीवन की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है।

बंद करने के लिए प्रेरित करना होगा। साथ ही, भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के पुनर्वास के लिए प्रभावी योजनाओं को लागू करना होगा। इसके लिए सरकार को शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर गरीबी और अशिक्षा को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाकर मानसिक विकारों से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करनी होगी। बाल शोषण रोकने के लिए सरकार को कड़े कानून बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए।

भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। इन लोगों को आश्रय, कौशल, शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। दरअसल, भिक्षावृत्ति एक जटिल समस्या है, जिसे हल करने के लिए सरकार को एक समग्र योजना बनानी होगी। लोगों को समझाना होगा कि भिक्षा देने से भिखारी आत्मनिर्भर नहीं बनते, बल्कि उनके जीवन की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है।

केंद्र सरकार ने भिक्षावृत्ति मुक्त भारत के लिए जिन तीस शहरों की सूची तैयार की गई है, उनमें धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन- तीन आधारों पर शहरों को चुना गया है। उनमें धार्मिक शहर अयोध्या, ओंकारेश्वर, कांगड़ा, सोमनाथ, उज्जैन, बोधगया, त्र्यंबकेश्वर, पावागढ़, मदुरै, गुवाहाटी हैं। पर्यटक शहर वारंगल, तेजपुर, कोझिकोड, अमृतसर, उदयपुर, कटक, इंदौर, मैसूर, पंचकूला और शिमला हैं। ऐतिहासिक शहरों में जैसलमेर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, कुशीनगर, सांची, केवडिया, श्रीनगर, नामसाई, खजुराहो, पुदुचेरी हैं। इन शहरों में भिक्षावृत्ति के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने और भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार कई उपाय कर रही है।

केंद्र सरकार ने भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के सर्वेक्षण और पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार करवाया है। इसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों का डाटा एकत्र करना और उनके पुनर्वास के लिए प्रभावी योजनाएं लागू करना है। इस पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से, जिला और नगर निगम अधिकारी इन शहरों में प्रमुख जगहों की पहचान कर सकते हैं, जहां लोग भीख मांगते हैं। सर्वेक्षण के दौरान भिखारियों से पूछा जाएगा कि क्या वे भीख मांगना छोड़ना चाहते हैं? इसकी जगह आजीविका के लिए वे क्या करना चाहते हैं? सर्वेक्षण के आधार पर, इन लोगों को पुनर्वास के लिए पात्रता के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। फिर पुनर्वास के लिए आश्रय, कौशल, शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस पोर्टल और मोबाइल ऐप पर चयनित शहरों में अधिकारियों को आश्रय, कौशल, शिक्षा और पुनर्वास प्रदान करने की प्रगति रपट डालनी होगी। इस पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

भारत में भिक्षावृत्ति से संबंधित कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है। हालांकि कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भिक्षावृत्ति को रोकने और नियंत्रित करने के लिए आधार के रूप में बांबे भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1959 का उपयोग करते हैं। यह कानून भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करता और पुलिस को बिना वारंट भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करने और उन्हें पुनर्वास केंद्रों में भेजने की शक्ति देता है। इस कानून की प्रभावशीलता पर भी अक्सर बहस होती रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कानून भिक्षावृत्ति को रोकने में प्रभावी नहीं हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह कानून भिक्षावृत्ति को कम करने में मददगार है। भिक्षावृत्ति की समस्या को कम करने के लिए कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ-साथ गरीबी, अशिक्षा और बाल शोषण जैसी समस्याओं को भी दूर करना बहुत आवश्यक है।

अवसाद का दुर्गम दौर

दुनिया मेरे आगे

अवनि सोमानी

वक्त का बीतना नियति है और अपने आरंभ के साथ ही यह बदस्तूर जारी है। समय और हालात ने हमारे दिलो-दिमाग का जायका जरूर बदला है, लेकिन हमारे पारंपरिक दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है। हालांकि वैयक्तिक सोच का अवमूल्यन अवश्य हुआ है, बावजूद इसके हम स्वयं में व्याप्त कमियों, खामियों, विसंगतियों और विकृतियों को स्वीकार करने से साफ-साफ कतराते रहे हैं। अब तो सब तरफ ही एक विचित्र सोच का सिलसिला चल पड़ा है। नैतिक और मानवीय मूल्य के कद्रदान तेजी से घटे हैं और पाशविकता और दैत्य प्रवृत्ति अप्रत्याशित रूप से पनपी है। जिंदगी कितनी जटिल हो गई है। मुकम्मल तौर पर कोई भी खुश और संतुष्ट नहीं। हर जगह बस त्राहि-त्राहि और बिगड़ा हुआ कुछ ठीक हो जाने की आस या फिर कुछ पा लेने की होड़। हालांकि न जिद और जुल्म से किसी का बेड़ा पार हुआ है और न ही स्वार्थ से कोई पनपा है। एक अजीब से इतिहास की संरचना में सभी प्रयासरत हैं।

कई बार ऐसा लगता है कि भय की भावना से उबर चुका है मानव मन। मगर क्या यह सचमुच भय से उबरना है? विश्वास, पूजा और आस्था अब कितने मूल रूप में कहां बचा है? क्या यह सच नहीं है कि इन मामलों में हम बेहद औपचारिक हो चले हैं। कसूरवार हम नहीं तो फिर और कौन है? अगर हम किसी और की ओर अंगुली उठाते हैं तो क्या वह सचमुच ऐसी हैसियत रखता है कि हम पर खुद को हावी कर ले? हमारे सवालों का जवाब शायद हमें पता होता है। मगर सच कब और किसने स्वीकार किया है? फैसला दर्ज है इधर अपने ही भीतर। यह जानकर भी सब अनजान बने हुए हैं। न उठते बवंडर के रुख का पता होता है और न ही स्पर्श और अहसास के संदर्भ ही ज्ञात हैं, लेकिन रास्ते की खोज और उसके बारे में पूछना जारी रहता है। गौर से देखें तो रास्ते सैकड़ों हैं, पर साथ ही अंधेरी तंग गलियों से गुजरना भी एक मजबूरी है।

वक्त से उसकी ताकत पूछने की भूल और हिमाकत कभी नहीं करनी चाहिए। वह शुरू से लेकर अब तक हर मौके पर साबित हुआ है कि वक्त क्या है और कितनी ताकत रखता है। सिद्धांतों और आदर्शों की बातें करते हुए अब सांस्कृतिक धरोहर पर इतराना भी छोड़ देना चाहिए।

विचित्र है कि भोगवादी संस्कृति हर जुल्म सहने को तैयार है। अंजाम चाहे जो भी हो, मन को मर्जी से और भावनाओं को यथार्थ तले दबना ही होगा। तैयार होती पृष्ठभूमि में बोध का महत्त्व कुछ ज्यादा ही है। अब परिभाषा में बंधने की कतई जरूरत नहीं। एक खुली किताब हमारे सामने है। इतिहास के पन्नों में सिमटती जिंदगी के हाशिये पर हमारी अच्छी-बुरी हर एक पहचान मौजूद है, जिसे स्वीकारने और नकारने की हिम्मत और क्षमता किसी में भी नहीं। अब बस समर्पण ही एकमात्र रास्ता लगता है और जो समर्पित होगा, उद्धार भी उसी का होगा। आज खोज उसकी है, जो वेदना में विलीन होती संवेदना की मजबूरी भी समझे। हम क्या चाहते हैं, यह खुद हमें ही ज्ञात नहीं। यह स्थिति कैसे और कहां से आई? इसमें बह जाने में हमारी कितनी भूमिका है? क्या कुछ ऐसा भी है जो सुचिंतित तरीके से हमारे सामने परोसा गया और हम उसके शिकार होते चले गए? मगर तब सवाल उठता है कि हमारी संवेदना के साथ हमारे विवेक का तालमेल कितना रहा!

दरअसल, स्नेह और सहानुभूति के लिए निरंतर तरसते इंसान के भीतर जिज्ञासाएं भी अनंत हैं। सभी हैरान और हतप्रभ दिखते हैं। पाखंडवाद और परंपरागत रूप से प्रगति पर दिख रहे हैं। मानदंडों की आधारशिला भी रखी जा चुकी लगती है। वक्त से उसकी ताकत पूछने की भूल और हिमाकत कभी नहीं करनी चाहिए। वह शुरू से लेकर अब तक हर मौके पर साबित हुआ है कि वक्त क्या है और कितनी ताकत रखता है। सिद्धांतों और आदर्शों की बातें करते हुए अब सांस्कृतिक धरोहर पर इतराना भी छोड़ देना चाहिए। मगर अपने आप से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। खुद को ठीक रखा जा सका तब अगर बहुतों को नहीं तो कुछ को जरूर संभाला जा सकेगा।

युग बदलने के साथ इतिहास भी बदला है। जमीन के यथार्थ को मीनार की ऊंचाइयों से मापने की आदत से हम बाज आ जाएं तभी अच्छा है। अक्षम्य कारस्तानियों के नीचे इंसानियत और मानवता का हर सुखद लम्हा दफन है। जिंदगी की उस रेखांकित इबारत पर नजर डाली जा सकती है, जो मुकम्मल मंजिल तलाशने के प्राथमिक प्रयास करती है। मगर यह असंभव है, क्योंकि आज हम अवसाद के दुर्गम दौर से गुजर रहे हैं और यह एक चुनौती भरी जटिल प्रक्रिया है। इंसान को इंसान से जोड़ने की बात पर जाने की जरूरत शायद बाद में पड़े, पहले अपने ही भीतर तहकीकात कर एक लंबा सफर तय करने की जरूरत है। सात्विकता की खोज में निरंतर भटक रहा हमारा थका-हारा और टूटा मन अब ठहराव चाहता है।

अगर अपनी ताकत और सीमा, दोनों की ईमानदार पहचान कर ली जाए तो चुनौतियों के सैलाब को पार करना कतई मुश्किल नहीं, पर संघर्षों का बीड़ा उठाने का कोई साहस भी तो करे! जिंदगी का अर्थ जानने का उत्साह किसी के भीतर देखने को नहीं मिलता, जबकि जिंदगी के अर्क में ही सारी सुखद और खुशनुमा अनुभूतियां छिपी हुई हैं। दरअसल, आज जरूरत यह जानने की नहीं कि जिंदगी ने हमें क्या दिया, बल्कि यह सोचने और समझने की है कि हमने जिंदगी को वास्तव में कैसे सजाया और संवारा है। ऐसे हर एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर आज हर आम इंसान लाचार और निरुत्तर-सा हो जाता है।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

आरोपों से आगे

हमारा देश इतनी प्रगति कर चुका है कि हम चांद-मंगल पर जाने की सिर्फ हसरत ही नहीं पालते, बल्कि ऐसा कारनामा कर चुके हैं। मगर जब किसी भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र भरे बाजार परीक्षा पूर्व बिकने की अपुष्ट खबर आती है। तब उन लाखों मेहनतकश अभ्यर्थियों का दिल हताश-निराश हो जाता है। उन्हें लगता है कि आखिर चांद-मंगल का सफर तय करने वाला हमारा देश एक त्रुटिहीन परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित नहीं कर पाता है! फिर वह हताश-निराश युवा जो कदम उठाता है, उससे दिल दहल उठता है, क्योंकि किसी की मेहनत की चोरी या उस पर डाका पड़ना अक्षम्य अपराध है।

दिलचस्प है कि नेता लच्छेदार भाषणों में आरोप-प्रत्यारोप कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेते हैं, जबकि दुरुस्त व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। राजस्थान में प्रश्न-पत्र लीक होने का मुद्दा भी बड़े नेताओं ने उठाया था और अब उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र बाहर आने की अपुष्ट खबर पर अन्य नेता हमला बोल रहे हैं। अंदाज दोनों का प्रभावी है। पर इससे उन अभ्यार्थियों की हताशा-निराशा का क्या?

- मुकेश कुमार मनन, पटना

पूर्वाग्रह का दंश

'पहचान और पूर्वाग्रह' (संपादकीय, 23 फरवरी) अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। वेश-भूषा और धर्म के आधार पर किसी जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी-अधिकारी की पहचान करना या उस पर किसी प्रकार का आक्षेप लगाना वर्तमान समय की सबसे बड़ी विडंबना और त्रासदी है। पर वस्तुस्थिति यह है कि आज के समय में बड़े से बड़े राजनेताओं से लेकर छोटे से छोटे सामान्य नागरिक तक हर कोई इस त्रासदी का शिकार है और इसका दंश भुगत रहा है। समाज में तेजी से बढ़ रहा विद्वेष और विभाजन इसी विडंबना का नतीजा है। कोई नहीं जानता कि यह बीमारी कहां जाकर रुकेगी, लेकिन सब जानते हैं कि इस तरह की नफरत की इस आंधी से कोई नहीं बच सकेगा। आवश्यकता इस बात की है कि 'पहचान और पूर्वाग्रह' के वर्तमान संकट का समुचित गंभीरता से संज्ञान लेकर पूरी दृढ़ता और ताकत से इसे रोका जाए। 'विविधता में एकता' हमारी सबसे बड़ी शक्ति और विशेषता है। इसलिए हर दृष्टि और हर कीमत पर इसकी सुरक्षा होना चाहिए।

- इशरत अली कादरी, खानूगांव

भ्रष्टाचार के विरुद्ध

भ्रष्ट तरीके से जमा किया गया धन और चुनावी चंदे का अभिन्न साथ है। न्यायपालिका ने चुनावी बांड पर प्रतिबंध लगाया तो यह आम जनता के हित में है, मगर राजनीतिक दल अब नया रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। चुनाव आयोग को उम्मीदवारों के लिए कुछ ऐसे सख्त नियम बनाने होंगे, जिससे चाह कर भी कोई दल काले धन का प्रयोग नहीं कर पाए! इसमें जनता को भी भागीदारी करनी होगी। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव जीतने के प्रयास को नकारते हुए ईमानदार प्रतिनिधियों का ही चुनाव करना चाहिए। जब मतदाता बेईमान उम्मीदवारों को नकारने लगेंगे तो राजनीतिक दलों को मजबूर होकर ईमानदार उम्मीदवारों को खड़ा करना पड़ेगा और बाहुबली और धनबलियों का प्रभाव धीरे-धीरे खत्म हो सकेगा!

- विभूति बुपक्या, खाचरोद, मप्र

महंगाई का दुश्चक्र

किसी भी बेहतर अर्थव्यवस्था का सबसे उम्दा पैमाना यह है कि वहां महंगाई की दर कैसी है और कितनी नियंत्रित है। वहां की आपूर्ति श्रृंखला कितनी बेहतर है, यह बहुत जरूरी है किसी देश को विकसित होने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बढ़ती महंगाई नियंत्रित नहीं हो रही है। हाल ही में आई बैंक आफ बड़ौदा की ताजा रपट में बताया गया है कि दुनिया भर में गेहूं के दाम 26 फीसद कम हुए हैं, जबकि भारत में आठ फीसद गेहूं महंगा हुआ है। इसके अलावा, विश्व जगत में प्राकृतिक गैस के दाम 54 फीसद घटे हैं और भारत में स्थिति उलट है। यहां पर 33 फीसद वृद्धि हुई है। सरकार को स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इससे निपटने का ठोस और दूरगामी उपाय निकालना चाहिए, अन्यथा बढ़ती महंगाई आम जनमानस पर एक प्रकार से टैक्स ही साबित होने वाला है।

- सौरभ बुंदेला, भोपाल

www.readwhere.com

पायनियर
नई दिल्ली, मंगलवार, 27 फरवरी, 2024

Join Magazine Group @ ₹60/m WhatsApp To 8969469464
Join Epaper Group @ ₹30/m WhatsApp To 8969469464

राजनीतिक पार्टियां

चुनावी वादे

हर चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टियां अनेक प्रकार के वादे करती हैं। इनमें से कुछ वास्तविक होते हैं, पर अधिकांश मतदाताओं को प्रसन्न करने के लिए लफ्फाजी की तरह होते हैं। चुनाव अभियान में किए इन वादों को चुनाव घोषणापत्र या चुनावी वादे या 'जुमले' भी कहा जा सकता है जिनको उस मौसम में स्थानीय मतदाताओं की महत्वाकांक्षाओं के अनुसार गढ़ा जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या पार्टियां ये वादे वास्तव में पूरा कर सकती हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त-सीईसी के अनुसार, मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि क्या ये वादे पूरे किए जाएंगे। सीईसी ने इस प्रकार चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबेही को रेखांकित करते हुए उम्मीद जताई है कि राजनीतिक पार्टियां पूरी जिम्मेदारी से वादे करेंगी। इस बहस के केन्द्र में राजनीतिक गत्यात्मकताओं, आर्थिक सीमाओं, प्रशासनिक क्षमताओं तथा सामाजिक उम्मीदों का जटिल अंतर्संबध है। राजनीतिक पार्टियां अक्सर अपने एजेंडे को चुनाव में विजय सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से बनाती हैं, जबकि चुनाव जीतने पर चुनावी वादे पूरे करने की व्यावहारिकता में असंख्य चुनौतियां सामने आती हैं। इनमें प्रशासन में अंतर्निहित अनिश्चितता तथा परिवर्तनशीलता भी शामिल है। राजनीतिक विमर्श लगातार विकसित हो रहा है और पार्टियों को स्वयं को इसके अनुसार ढालना होता है। इस कारण अक्सर वे उन मुद्दों पर पीछे हट जाती हैं जिनकी पहले जोरदार पैरवी कर रही थीं। इसके साथ ही अनुमान से परे घटनायें, आर्थिक उतार-चढ़ाव तथा वैश्विक गत्यात्मकतायें भी चुनावी वादे पूरा करना कठिन बना सकती हैं।

चुनाव अभियान के समय जो संभव लगता है वह उभरती चुनौतियों को देखते हुए असंभव हो जाता है। इस समस्या से निपटने का रास्ता सबसे अच्छा पार्टियों द्वारा यह घोषणा करना होगा कि 'यह हमारा इरादा है, पर कुछ शर्तें लागू होती हैं।' इस प्रकार की ईमानदार घोषणा से कम से कम यह संदेह नहीं होगा कि वादे पूरे ही किए जाएंगे। हालांकि, मतदाता भी जानते हैं कि कुछ वादे पूरे नहीं किए जा सकते हैं, पर उनके सामने ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं। ऐसा खासकर इसलिए होता है कि प्रतिद्वंद्वी पार्टी भी ऐसी ही योजनायें पेश करती है जिनको पूरा नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से ईमानदारी से किए वादों के सामने भी ऐसी गंभीर चुनौतियां आ सकती हैं जिनका पहले अनुमान लगाना संभव न रहा हो, लेकिन समस्या उस समय पैदा होती है जब वोट पाने के लिए जानबूझ कर भ्रामक या गलत वादे किए जाते हैं। इससे भी बुरी बात पार्टियों की यह समझ है कि इस व्यवहार के लिए उनको कोई दंड नहीं मिलेगा। इन स्थितियों को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों द्वारा ज्यादा जिम्मेदारी का व्यवहार करना जरूरी हो गया है। लोकरंजक लफ्फाजी के बजाय उनको ईमानदारी, यथार्थ तथा प्रमाण-आधारित नीति निर्माण का व्यवहार करना चाहिए। पारदर्शिता भी जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि इन वादों के पीछे क्या तार्किकता है और इनका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। इसके साथ ही प्रगति का मूल्यांकन करने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि सरकारों को उनकी पार्टी की प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके। चुनावी वादे पूरा कराने के लिए ज्यादा जन जागरूकता जरूरी है। नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता कर प्रतिनिधियों को उनके कामों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। ऐसे में जानबूझ कर गलत वादे करने वालों को मतदान के माध्यम से दंड दिया जा सकेगा।

शिक्षा व्यवस्थाः संपूर्णता की खोज

भारतीय शिक्षा व्यवस्था आज महत्वपूर्ण मोड़ पर है। वह अपनी पहचान स्थापित करने के साथ अंतर्निहित क्षमताओं को खोज कर संपूर्णता की ओर बढ़ रही है।

जे.एस. राजपूत
(लेखक, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं)

भारतीय शिक्षा व्यवस्था आज महत्वपूर्ण मोड़ पर है। वह अपनी पहचान स्थापित करने के साथ अंतर्निहित क्षमताओं को खोज कर संपूर्णता की ओर बढ़ रही है। शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र में वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां रेखांकित करने के लिए अतीत में लंबे समय तक व्याप्त रही स्थितियों पर नजर डालना जरूरी है। शिक्षा क्षेत्र में लंबे समय तक व्याप्त रही परिस्थितियों तथा उसकी वर्तमान उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के दृष्टिकोण से ऐसे परिपक्व अकादमीशियनों, विद्वानों तथा नीति निर्माताओं की टिप्पणियों पर गौर किया जाना चाहिए जिन्होंने तीन-चार दशक तक नीति निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों की ओर से सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में शिक्षा के प्रति परिवर्तन के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है।

शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक गंभीर बाधा व्यक्ति व परिवार के जीवन में शिक्षा मूल्य के प्रति अज्ञान रहा है। क्या ऐसे समाज से ज्यादा उम्मीद की जा सकती है जो शताब्दियों तक अंधकार में डूबी रही तथा उसे अपने जीवन में भयानक गरीबी का सामना करना पड़ा। सामाजिक ढांचों में पृथक्करण, महिलाओं की भूमिका के बारे में बहुत गलत अनुमान व महिला साक्षरता से इसके संबंध तथा लड़कियों की शिक्षा को कमतर मानने वाले अनेक धर्मगुरुओं के विचारों के कारण लड़कियों की शिक्षा में अनेक बाधायें आ गई थीं। यह स्थितियां उन संवैधानिक निर्देशों के पहले व्याप्त थीं जिनतें सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने को मुख्य लक्ष्य माना गया। जल्दी विवाह की प्रचलित परंपरा के साथ ही बाल श्रम, रोज कमाई की मजबूरी तथा खेतों और कार्यस्थलों पर अतिरिक्त श्रम की आवयकता ने भी स्कूलों में दाखिले पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाला था। आज की पीढ़ी के लिए ऐसी स्थिति की कल्पना करना कठिन है जब दशकों तक भारत में लड़कियों की शिक्षा स्कूलों में लड़कियों के शौचालय न होने से प्रभावित होती थी। यह उन क्षेत्रों में से केवल एक है जिनको लगातार अनदेखा किया गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता व्यवहारों पर जोर देने के बाद तत्काल सुधार की आवश्यकता अनुभव की गई। इससे चीजों में व्यापक परिवर्तन आया और इस कदम की प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन इस विषय पर अब भी जागरूकता तथा जोर देने की आवश्यकता बनी हुई है। मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि व्यक्तिगत संवाद से जो चीजें सामने आती हैं उनकी अभिव्यक्ति आंकड़ों के माध्यम से होना जरूरी नहीं है। 2016 में शिक्षा नीति पर टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी के सदस्य के रूप में अनेक संस्थानों का दौरा करने का अवसर मिला। लगभग दो हजार दाखिले वाले एक कालेज में जब सफाई की अनदेखी का सवाल उठा तो निदेशक को कहना पड़ा कि इतनी गंदगी और अस्वास्थ्यकर स्थितियां हैं कि मेरा निरीक्षण करना असंभव है। मैंने इस घटना का उल्लेख दो कारणों से किया है। पहला, शिक्षा व्यवस्था ने इस महत्वपूर्ण बाधा पर बहुत कम ध्यान दिया। दूसरा, स्वच्छता की सार्विक स्वीकार्यता और उसकी व्यापक सफलता के बाद भी इस मोर्चे पर अभी बहुत काम करना बाकी है। वर्तमान समय में हम शिक्षा उपलब्धियों के बारे में महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। यह बात खासकर लड़कियों की शिक्षा तथा ज्ञान के हर क्षेत्र, कौशल, सेवाओं, रक्षा, आदि के बारे में सही है। सवाल है कि बीसवीं शताब्दी के दूसरे अर्धांश में भारतीय शिक्षा में सर्वाधिक अनदेखा वाला कौन सा क्षेत्र था? कुछ अकादमीशियन और विद्वान तथा नकारात्मकता से भरे लोग इस कालखंड में हुए काम और उपलब्धियों की आलोचना करेंगे। लेकिन वैचारिक रूप से बाधाओं से मुक्त तथा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में सक्षम लोग ऐसे कुछ आयामों की आलोचना करेंगे जिनका संबंध किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास से है। आमतौर से ऐसा हर नीति और कार्यक्रम के बारे में होता है, पर वर्तमान शिक्षा व्यवहारों की अनदेखी कुछ स्कूलों तथा अनेक सम्मानित संस्थाओं में भी हो रही है। शिक्षा के नैतिक एवं आदर्श आयाम, मानव मूल्यों की शिक्षा तथा हर शिक्षा पहल में ऐसी अभिव्यक्तियां सामान्य रूप से आती हैं।

हमारे पास महात्मा गांधी की विरासत है जो कहते थे कि 'मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।' हमारी वर्तमान पीढ़ी के कितने नेता पूरी प्रतिबद्धता और विश्वास के साथ यही बात कह सकते हैं? आज भी ऐसे पुराने और नए लोग हैं जो महात्मा गांधी, राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, नरेन्द्र मोदी तथा ऐसे ही लोगों को अपना 'रोल माडल' मानते हैं। एक प्रतिबद्ध कार्य संस्कृति, एक गंभीर मूल्य प्रणाली और उच्च व व्यापक लक्ष्यों की खोज को केवल शिक्षा संस्थानों द्वारा ही जीवन में समाहित किया जा सकता है और यही भारतीय शिक्षा व्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हम इस मामले में लाभ की स्थिति में हैं कि इसे प्राप्त करने के तरीकों से हमारा परिचय है। भारतीय शिक्षा को देश के भीतर तथा बाहर समुचित स्वीकार्यता तथा उपलब्धियां प्राप्त करने में सफलता मिली है। भारत और उसकी प्राचीन शिक्षा व्यवस्थाओं का उद्देश्य समग्र व्यक्तित्व का विकास था। इसके पीछे 'एकं सद् विप्राः बहुधा वदन्ति', 'सर्व भूत हिते रतः', 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' तथा ऐसे ही अनेक विचार निहित हैं। इनका अर्थ है कि सत्य एक है, पर विद्वान उसे अनेक प्रकार से कहते हैं। हमें सभी जीवों के हित में निरंतर सक्रिय रहना चाहिए तथा सभी लोग प्रसन्न हों। भारतीय मनीषियों की ये तथा अनेक अन्य अवधारणायें तत्कालीन समाज के जीवन और शिक्षा में अंतर्निहित थीं। कालान्तर में अनेक कारणों से ये विलुप्त होती गईं अथवा दासता व अंधकारमय परिस्थितियों के कारण इनको समाज में लागू नहीं किया जा सका। स्वतंत्रता आंदोलन के समय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के लिए आदर्श शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की थी और उसके मानक भी रेखांकित किए थे।

हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी ने हमें शिक्षा का ऐसा व्यावहारिक माडल दिया था जिसमें आर्थिक आयाम शामिल थे, पर वह समग्रता को अनदेखा नहीं करता था। गांधीजी चाहते थे हमें दिल, दिमाग और हाथों से सवोच्च उपलब्धियां प्राप्त करनी चाहिए। श्री अरविंद तथा पूज्य माताजी ने शिक्षा के सामान्य लक्ष्यों के साथ ही मानव विकास के उच्च आयामों की कल्पना कर उनको जीवन में उतारने के प्रयास किए थे। यह सत्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि हमारी शिक्षा की पहलें और प्रयास शिक्षा के माध्यम से भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करने पर अधिक केन्द्रित रहे हैं।

माताजी ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सीखने वालों को इस जीवन व समाज के लिए तैयार करना ही नहीं, बल्कि 'उनकी संपूर्णता को बढ़ावा देना है।' आश्रम स्कूलों के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, 'केवल सफलता को लक्ष्य न बनाएं। हमारा उद्देश्य संपूर्णता है। याद रखें कि आप नई दुनिया में हैं, उसमें सहभागिता कर रहे हैं तथा उसकी रचना में सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में परिवर्तन से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है।' माताजी ने हमें समझाने के लिए आगे कहा था, शिक्षा का उद्देश्य 'ज्ञान प्राप्त करने के लिए सीखना, प्रकृति व जीवन के रहस्यों को जानने के लिए अध्ययन, अपनी चेतना जाग्रत करने के लिए स्वयं को शिक्षित करना, अपना स्वामी स्वयं बनने के लिए स्वयं को अनुशासित करना, अपनी कमजोरियों व अक्षमताओं एवं अज्ञान से मुक्ति पाना, स्वयं को भावी जीवन के लिए तैयार करना ऐसा लक्ष्य है जो ज्यादा आदर्श, व्यापक, ज्यादा उदार तथा ज्यादा सच है।'

शिक्षा के उद्देश्यों पर गौर करते हुए क्या हमारे स्कूलों और शिक्षा संस्थानों के लिए इससे अच्छी कोई बात कही जा सकती है। हमें महात्मा गांधी, श्री अरविंद तथा माताजी के विचारों पर गौर करते हुए उनके कथनों में छिपे दर्शन की शक्ति के अनुसार शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना होगा।

अपराध संहिताओं में संशोधन के प्रभाव

"पिछले साल पारित दो निर्णयों का विश्लेषण करके हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जांच एजेंसी का पक्ष लेने की ओर झुकाव बढ़ रहा है।"

प्रखर बाजपेयी
(लेखक, विधि के छात्र हैं)

संसद ने तीन आपराधिक संहिताएं पारित की हैं, जिनमें से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) में संशोधन करना चाहती है। बीएनएसएस में एक प्रावधान है जो उन दिनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करता है जिनके भीतर पुलिस हिरासत (पीसी) की मांग की जा सकती है। जब कोई पुलिस हिरासत में होता है, तो इसका मतलब है कि उसे पुलिस ने स्टेशन के लॉकअप में रखा है। दूसरी ओर, न्यायिक हिरासत का मतलब है कि उन्हें के केंद्रीय जेल में रखा जाएगा।

जांच एजेंसी को जांच करने के लिए 24 घंटे मिलते हैं यदि वे उस सीमा के भीतर जांच पूरी करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी, जो मामले की गंभीरता के आधार पर आरोपी को 60/90 दिनों तक की हिरासत दे सकता है।

हालांकि, 60/90 दिनों की इस समय सीमा के भीतर, मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी की तारीख से शुरुआती 15 दिनों के लिए पीसी देने तक सीमित है, जिसके बाद के वल न्यायिक हिरासत दी जा सकती है। इस 15 दिन की सीमा पर अनुपम कुलकर्णी बनाम सीबीआई मामले में व्यापक रूप से चर्चा की गई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किसी आरोपी को गिरफ्तारी की तारीख से 15 दिनों से अधिक पीसी में नहीं रखा जा सकता है और पीसी कुल मिलाकर अधिकतम 15 दिनों के लिए हो सकती है। जिसका अर्थ है कि मजिस्ट्रेट द्वारा पीसी को पहले 15 दिनों के लिए भागों में या संपूर्ण रूप से प्रदान किया जा सकता है।

बीएनएसएस की धारा 187 के अनुसार, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पहले 40 दिनों (कम गंभीर अपराधों के लिए) या 60 दिनों (अधिक गंभीर अपराधों के लिए) के भीतर पीसी दी जा सकती है। परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि हिरासत की निर्धारित 15-दिन की

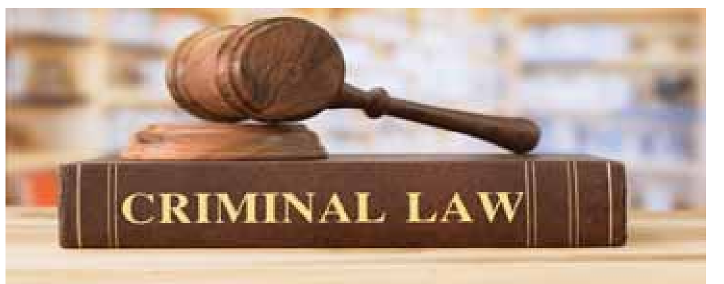

अवधि को अब 10 साल तक की सजा वाले अपराधों के लिए 40 दिनों या अन्य अपराधों के लिए 60 दिनों की हिरासत की छोटी अवधि में विभाजित किया जा सकता है। यह सीआरपीसी की धारा 167 के तहत मौजूदा प्रथा से विचलन का प्रतिनिधित्व करता है, जहां पीसी के वल शुरुआती 15 दिनों के भीतर ही प्राप्त किया जा सकता है। नतीजतन, इस बदलाव के पीछे सरकार के तर्क के बारे में चिंताएं उठाई गई हैं, विशेष रूप से जन-के ंद्रित आपराधिक न्याय प्रणाली को प्राथमिकता देने के अधिनियम के उद्देश्य पर विचार करते हुए। हालांकि, आगे की दलीलों के लिए दो महत्वपूर्ण मामलों की जांच की आवश्यकता है। निर्णय जो विरोधाभास की ओर ले गए- सबसे पहले, विकास मिश्रा बनाम सीबीआई के मामले में, जहां सीबीआई विकास मिश्रा से पूछताछ करने के लिए अधिक समय चाहती थी, जिस पर भ्रष्टाचार और साजिश का आरोप था। सात दिनों तक हिरासत में रहने के बावजूद, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। सीबीआई ने दलील दी कि इस दौरान वे उनसे ठीक से पूछताछ नहीं कर सके . हालाँकि, विकास के वकीलों ने अदालत के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि गिरफ्तारी की तारीख से 15 दिनों से अधिक पीसी की अनुमति नहीं है। बहरहाल, अदालत ने पुलिस को हिरासत दे दी और कहा कि प्रत्येक आरोपी व्यक्ति को जांच और अदालती कार्यवाही का सम्मान करना चाहिए और यह भी उल्लेख किया कि न्याय की खोज में बाधा डालने के इन तरीकों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा, सेंथिल बालाजी बनाम राज्य के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अधिकतम 15 दिनों की पीसी अवधि को पूरी जांच में छोटी अवधि में विभाजित किया जा सकता है, जो अनुदान देने के सामान्य नियम के विपरीत 60 या 90 दिनों तक चल सकता है। पहले 15 दिनों में पीसी ने अनुपम कुलकर्णी के फैसले पर भी सवाल उठाया और आगे कहा कि इस व्याख्या की एक बड़ी पीठ द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। पिछले साल पारित दो निर्णयों का विश्लेषण करके हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जांच एजेंसी का पक्ष लेने की ओर झुकाव बढ़ रहा है।

चिकित्सीय कारणों से पहले मामले में आरोपी द्वारा प्रारंभिक पीसी से बचने का प्रयास करने के बावजूद, यह पहचानना जरूरी है कि आरोपी मेडिकल आपातकाल के आधार पर खामियों का बहाना लेकर 15 दिन की रोक का फायदा उठा सकता है।

हालांकि, दूसरा मामला जांच प्रक्रिया को आपराधिक न्याय प्रणाली के के ंद्र में रखते हुए एक मिसाल कायम करता है जो विसंगतियों की एक संभावित श्रृंखला पैदा करता है। इसलिए, बीएनएसएस की धारा 187 का लक्ष्य मौजूदा भ्रम को निश्चित रूप से हल करना और समयसीमा के संबंध में भविष्य की विसंगतियों को रोकना है जिसके भीतर पीसी की मांग की जा सकती है और 40/60 दिनों की सीमा निर्धारित की गई है।

यह एक मध्य मार्ग खोजने का प्रयास करता है जहां अभियुक्तों की नागरिक स्वतंत्रता का शोषण नहीं किया जाता है क्योंकि अधिकतम दिनों के लिए पीसी दी जा सकती है जो अभी भी 15 दिन है जिसे अब 40/60 दिनों में भागों में प्रदान किया जा सकता है और यह जांच का भी समर्थन करता है। एजेंसियों को हिरासत में पूछताछ के लिए उचित समय देना चाहिए, जो सच्चाई को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जांच एजेंसी को आगे की पूछताछ के अवसर से वंचित करने से आरोपी को कानूनी प्रक्रिया को बाधित करने का लाभ मिलता है।

आप की बात

ब्रिटेन में इस्लामवाद

ब्रिटिश समाज दुनिया में सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष समाजों में से एक माना जाता है। कई सर्वेक्षणों में यहां नास्तिकता, संदेहवाद, मानवतावाद व धार्मिक मान्यताओं से दूरी के विचार मिले हैं। लेकिन अब सत्तारूढ़ कन्जर्वेटिव सांसद ली एंडरसन ने आरोप लगाया है कि इस्लामवादियों ने लंदन के मेयर सादिक़ खान पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि इस बयान पर कंजर्वेटिव पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया है, पर इससे ब्रिटेन में जारी उथलपुथल का पता चलता है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्टीकरण भी दिया कि अभी इस्लामवादियों का पूरे देश पर नियंत्रण नहीं हुआ है। ब्रिटेन में धार्मिक उदारता के चलते ही देश की जनता ने सर साजिद जावेद को स्वास्थ्य मंत्री, स्कॉटलैंड में हम्ज़ा यूसुफ़ को मंत्री तथा हिन्दू ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जहां कट्टरपंथी मुसलमानों ने कथित शरीया क्षेत्र बना कर वहां शरीया लागू करने के प्रयास किए, वहीं 9-11 तथा अन्य आतंकी हमलों के बाद ब्रिटिश समाज के कुछ तबकों में मुस्लिमों के प्रति घृणा की भावना पैदा हुई जिसका शिकार कुछ सिखों को भी बनना पड़ा क्योंकि अनेक लोग सिखों और मुसलमानों में अंतर नहीं कर पा रहे थे। यह स्थिति चिन्ताजनक है।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

योगी की चेतावनी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षाओं में सेंध लगाने वालो को चेतावनी देते हुए कहा कि युवाओ के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालो को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वे घर के रहेंगे न घाट के। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल, पेपर आउट और धांधली की घटनाएं दूसरे राज्यों में भी पिछले कई वर्षों से हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिये केंद्र सरकार ने सख्त कानून बनाया है। मुख्यमंत्री योगी ने परीक्षाओं में सेंध लगाने को राष्ट्रीय पाप बताते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रियाओं में विलम्ब से युवाओं के साथ होने वाला खिलवाड़ प्रतिभा पलायन को मजबूर करता है। परीक्षाओं में पेपर लीक होना चिंतनीय मुद्दा है। सरकार को गौर करना होगा कि धांधली किस स्तर से हुई है। इसका पता लगाकर धांधली में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और सजा का सन्देश समाज में जा कर नकल माफिया को हतोत्साहित कर सकता है। सरकार को प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर सरकारी प्रेस में छपवाने तथा पुलिस के माध्यम से उनके वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए। छात्रों-नौजवानों को उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ नकल माफिया का सफाया कर देश-प्रदेश के समक्ष उदाहरण पेश करेंगे।

– **कुलदीप मोहन त्रिवेदी,** उन्नाव

भोजन बनाने की कला

भोजन जीवन का अनिवार्य अंग है। स्वादिष्ट व भर पेट मनपसंद भोजन करना सबकी इच्छा होती है। मगर इसे बनाने का काम केवल महिलाओं के लिए छोड़ने की सोच के चलते लड़कों और युवकों को खाना बनाना सीखने में दिलचस्पी नहीं होती है। समाज में मर्दों द्वारा खाना बनाना कभी हेय दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज खाना बनाने वाले नामी शैफ सेलिब्रिटी बने हुए हैं जिनमें अधिकांश पुरुष हैं। इस प्रकार महिला का कौशल माने जाने वाले इस क्षेत्र पर पुरुषों ने कब्जा कर लिया है। मां के हाथ का खाना आदमी आजीवन नहीं भूलता है। मगर मां के चले जाने के बाद तथा अन्य कारणों से मजबूरी में होटलों का खाना खाना पड़ता है। एक और हैरानी की बात है कि जहां अनेक युवकों ने खाना बनाना सीखना शुरू किया तो अनेक युवतियों ने इसे सीखना बंद कर दिया है। ऐसे में बेहतर विकल्प यही है युवक और युवतियां खाना बनाना सीखें तथा उसमें परस्पर सहयोग करें। अनेक गांधीवादी, सर्वोदयी व विनोबा भावे के अनुयाई पाक-कला को एक आवश्यक जीवन कौशल मानते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विभिन्न अभियानों में वे इसका समुचित उपयोग करते थे। पाक-कला को जीवनकौशल की मान्यता देने का समय आ गया है।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

संवेदनहीन ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राज है। लेकिन वहीं के गाँव संदेशखाली में अनेक महिलाओं को दुष्कर्म और भयानक अत्याचार का शिकार होना पड़ा। वे इतनी भयभीत हैं कि प्रशासन के सामने मुंह तक नहीं खोल रही हैं। देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के राज में सत्ता-संरक्षित बाहुबलियों के अत्याचार से महिलायें इतनी उत्पीड़ित व भयभीत हैं। शाहजहां शेख तथा उसके समर्थक गुंडों को सत्तारूढ़ टीएमसी का खुला समर्थन प्राप्त है और इसी कारण उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ममता बनर्जी भले ही सुशासन की बात करती हों, पर वह गरीब महिलाओं के प्रति पूर्णतः सेवेदनहीन हैं और केवल सत्ता में बनी रहना चाहती है। वे विपक्ष पर झगड़े-दंगे का आरोप लगा देती हैं, पर अपने समर्थक बाहुबलियों को खुला संरक्षण देती हैं। इस मामले में यूपी योगी सरकार की प्रशसा होती है जिसने बाहुबलियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। विडंबना है कि बंगाल में गठबंधन के प्रयास में लगी कांग्रेस और माकपा भी ममता बनर्जी के खिलाफ मुखर नहीं हो रहे है। ऐसी संकुचित व दलगत चुनावी राजनीति से किसी को कोई लाभ नहीं होगा।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण

परिश्रम से संपत्ति बढ़ती है और आलस्य से दरिद्रता

विदेश में नौकरी का लालच

यह अच्छी खबर है कि यूक्रेन में युद्ध लड़ रही अपनी सेना के लिए काम करने वाले भारतीय युवकों को रूस ने कार्यमुक्त करना शुरू कर दिया और उनमें से कुछ स्वदेश लौट भी आए। आशा है कि शीघ्र ही ऐसे सभी युवक अपने घर आ जाएंगे, जिन्हें धोखे से रूस ले जाकर वहां की सेना के साथ खपा दिया गया था। उनसे वादा तो किसी और नौकरी का किया गया था, लेकिन उन्हें सैनिक के तौर पर युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया, जहां उनकी जान पर बन आई। रूस के मित्र देश होने के कारण इन युवकों को बचाने में आसानी हुई, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारत अब कहीं भी कठिनाई में फंसे अपने लोगों को स्वदेश लाने में सफल रहता है। हाल में कतर में मौत की सजा पाए नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को मुक्त कराने में सफलता मिली थी। एक समय यह बेहद कठिन दिख रहा था। करीब एक वर्ष पूर्व हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकाला गया था। इसके पहले लीबिया, यमन, यूक्रेन आदि से भी उन्हें बचाकर लाया जा चुका है, लेकिन कभी-कभी तब अनहोनी हो जाती है, जब भारतीय ऐसे किसी देश में चले जाते हैं, जहां खतरा अधिक होता है। कुछ वर्ष पहले इराक गए भारतीय युवक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का निशाना बन गए थे।

यह ठीक नहीं कि कई बार भारतीय अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना ऐसे देश भी चले जाते हैं, जो अस्थिरता और अराजकता से ग्रस्त होते हैं। बेहतर कमाई के लिए विदेश जाना अब कोई नई-अनोखी बात नहीं, लेकिन लोगों को इसकी छानबीन तो करनी ही चाहिए कि उन्हें बाहर भेजने वाले विश्वसनीय हैं या नहीं? अच्छा हो कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जिन्होंने भारतीय युवकों को धोखे से रूस भेज दिया। यह चिंताजनक है कि विदेश में नौकरी का लालच देकर लोगों को अवैध तरीके से ले जाने या फिर उनके साथ ठगी करने वालों के गिरोह बन गए हैं। अभी हाल में दुबई से निकारागुआ जा रहे एक विमान को मानव तस्करी के संदेह में फ्रांस ने रोक लिया था। मोदी सरकार इस विमान में सवार करीब तीन सौ भारतीयों को स्वदेश लाने में सफल रही थी। इनमें अधिकतर पंजाब के थे, जहां के लोग विदेश जाने के लिए हर तरह का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। एक ओर जहां यह आवश्यक है कि सरकारें विदेश में नौकरी के नाम पर छल-कपट करने वाले तत्वों पर शिकंजा कसें, वहीं दूसरी ओर लोगों को भी सतर्क रहना होगा और खतरा उठाने से बचना होगा। विदेश में नौकरी के लिए संदिग्ध तत्वों की सहायता लेना या फिर अवैध तरीके अपनाना एक तरह से जानबूझकर जोखिम मोल लेना है। जब सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक लोगों की सहायता के उपाय कर रखे हैं तो फिर इसका कोई औचित्य नहीं कि उनकी अनदेखी की जाए।

हथियारों की तस्करी

पंजाब में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हथियारों की तस्करी की समस्या बढ़ती जा रही है। जाहिर है कि ये हथियार किसी नेक कार्य के लिए तो मंगवाए नहीं जा रहे, अपितु अपराधी इनके माध्यम से हत्या जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गत दिवस पटियाला में पुलिस ने एक ऐसे ही अपराधी को गिरफ्तार किया जो उत्तर प्रदेश से हथियार लाकर पंजाब में बेचता था। उससे पिस्टल, रिवाल्वर और कारतूस भी बरामद हुए हैं। हैरत और चिंता की बात यह है कि इस आरोपित को वर्ष 2022 में भी रूपनगर की पुलिस ने हथियारों की आपूर्ति के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहां की अदालत से भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद भी आरोपित अवैध रूप से हथियारों की आपूर्ति का काम कर रहा था। यह कहीं न कहीं पुलिस की विफलता और सूचना तंत्र की कमजोरी का भी परिणाम है कि एक भगोड़ा पुलिस की पहुंच से दूर रहकर अपराध में लगा रहा। एक राज्य से दूसरे राज्य तक अवैध हथियार लेकर आखिर वह कैसे पहुंचता रहा, वह भी तब जबकि वह पुलिस और न्यायालय को वांछित था। इस आशंका से इन्कार नहीं कर सकते कि उसने बड़ी संख्या में पंजाब के अपराधियों तक हथियार पहुंचाए होंगे। पुलिस को इस पूरे मामले की तह तक जाना होगा और जिन अपराधियों तक हथियार पहुंचाए गए हैं, उन पर भी शिकंजा कसना होगा। इस मामले में पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। नागरिक समाज में आम लोगों के बीच हथियारों का बढ़ना कानून-व्यवस्था और शांति के हित में नहीं है।

यह पुलिस की विफलता एवं सूचना तंत्र की कमजोरी का ही परिणाम है कि भगोड़ा अपराधी लगातार हथियार तस्करी करता रहा एवं पुलिस पकड़ नहीं पाई

विश्व शांति-सद्भाव की नई आस

विकास सारस्वत

दुनिया में शांति और सौहार्द की बहाली में बहुईश्वरवाद वाले देशज धर्मों की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है

भारत सहित कई देशों में इस समय पुरातन गौरव, देशज संस्कृति एवं धर्म विचार-विमर्श के केंद्र बिंदु बन रहे हैं। इसके चलते देशज धर्मानुयायी विश्व मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस कड़ी में कुछ समय पहले असम के डिब्रूगढ़ में विश्व भर के देशज धर्मों का एक महासम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में 33 देशों से आए 400 प्रतिभागियों ने प्राचीन जीवन परंपराओं के महत्व पर चर्चा की। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दुनिया भर के स्वदेशी धर्मों को पुनर्जीवित करने और उनकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का संकल्प दोहराया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने ज्ञान-विज्ञान के प्रसार के बावजूद दुनिया भर में चल रहे संघर्ष और सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। संघ प्रमुख ने भौतिक प्रगति के बावजूद कायम वैश्विक संघर्ष का कारण अध्यात्म के अभाव और धार्मिक चेतना के ह्रास को बताया। सम्मेलन में इस चिंता की स्वीकृति और उससे लड़ने में स्वदेशी धर्मों की प्रासंगिकता का उद्धरण विभिन्न धर्मों के अनुष्ठानों में प्रकृति पूजन की समरूपता में दिखा। कार्यक्रम का स्वस्तिवाचन एक यजीदी बुजुर्ग द्वारा पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, जल एवं पक्षियों के स्तुतिगान से हुआ। एक कैरेबियन बुजुर्ग ने अपने पारंपरिक अनुष्ठान में जल और पौधे का अभिषेक किया। अरुणाचल प्रदेश की न्यीशी जनजाति ने सूर्य भगवान की उपासना में भजन गाया। एक ही मंच से सात महाद्वीपों के आठ धर्मानुयायियों द्वारा वैश्विक कल्याण के लिए किया गया अनुष्ठान विविधता में एकता, वैश्विक भाईचारे और धार्मिक मूल्यों की सार्वभौमिकता को तो प्रदर्शित कर ही रहा था, इस पर भी सोचने को विवश करता था कि एकेश्वरवादी इब्राहिमी मतों ने प्राचीन विश्व को कितना बदल दिया है।

एकेश्वरवाद के प्रसार और प्राबल्य द्वारा पैदा हुए संघर्ष के बावजूद इस विषय पर बौद्धिक विमर्श प्रायः लुप्त है। मानव इतिहास ने व्यक्तिगत अहं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और द्वेष के कारण तमाम युद्ध झेले, किंतु केवल अपने ही ईश्वर को दुनिया के हर व्यक्ति द्वारा सच्चा मनवाने के दुराग्रह ने सर्वाधिक रक्तपात किया। कथित दैवीय आदेश के पालन का दावा कर अपने एक ईश्वर के लिए दुनिया जीत लेने की जिद ने ऐसे संघर्षों को जन्म दिया, जो दो-चार पीढ़ी से नहीं, बल्कि सदियों से चले आ रहे हैं और इनके भविष्य में भी समाप्त होने के आसार नहीं। एकेश्वरवादी कट्टरता ने हिंसा और मतांतरण के जुनून द्वारा एशिया से लेकर अमेरिकी महाद्वीपों तक सभ्यताओं को नष्ट किया है। अपनी एकमेव ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार न करने के चलते इन मतों ने न सिर्फ मानवता को 'विश्वासी' बनाम 'अविश्वासी' जैसी व्यष्टि में बांटा, बल्कि अविश्वासी करार दिए गए समूहों को नीचा एवं पतित बताकर मानवता का अवमूल्यन भी किया। अविश्वासी समूहों के लिये पैगन, हीथन और काफिर जैसा शब्द प्रयोग घृणा और तुच्छता के भाव से प्रेरित था। इनका आशय ऐसे असभ्य, अज्ञानी लोगों से है, जो मूर्तिपूजक होने के नाते आसुरी प्रवृत्ति के हैं। भारतीय उपमहाद्वीप से बंदी बनाई गई महिलाओं-बच्चों का पश्चिम एशियाई बाजारों में बेचा जाना और अफ्रीका से अश्वेत लोगों को पकड़ कर अमेरिकी गुलामी में धकेलना 'अविश्वासी' लोगों के अवमूल्यन के कारण ही सहज उद्यम बन पाया।

अवधेश राजपूत

एक जनसमूह को हीन समझकर अपने विरोध में स्थापित करने वाली दुर्भावना, जिसे प्राच्यवादी विचारक एडवर्ड सईद ने अन्यीकरण या 'अदरार्ईजेशन' का नाम दिया, वह असल में एकेश्वरवादी मतों की कट्टरता से ही जन्मी। संपूर्ण मानवता को एकरूपता में ढालने का उद्देश्य रखने वाले मार्क्सवाद को भी कई बार ईसाइयत का मतांतर ही माना जाता है। इसकी पुष्टि मार्क्सवाद का वह खाका भी करता है, जो अन्य इब्राहिमी मतों की तरह 'हमारे साथ नहीं हैं तो आप हमारे विरुद्ध हैं' जैसे सोच में बंधा हुआ है। इसकी तुलना में बहुईश्वरवादी भारत-सद्भाव और सहिष्णुता का प्रतिमान रहा है। यही नहीं, मिस्र, रोम, ग्रीस, फारस, बेबीलान और चीन आदि विश्व की सभी महान सभ्यताएं बहुईश्वरवादी रही हैं। कभी फैरो अखेनातेन जैसे शासक ने क्रूर एकेश्वरवाद थोपा भी तो जनता ने उसकी मृत्यु उपरांत उसे खारिज कर दिया। इस्लाम से पहले का अरब भी बहुईश्वरवादी होने के नाते धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। जिस काबे में आज गैर-मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, वहां सभी अरब कबीलों के ग्राम देवताओं का एक ही प्रांगण में वास था। बहुईश्वरवादी पुरातन सभ्यताओं में दूसरी सभ्यताओं के ईश्वरों के लिए भी सम्मान था। विजयी यवनों के आगमन के बाद गंधार कला शैली में ग्रीक प्रतिमानों में बनी बुद्ध की तमाम मूर्तियां इसका उदाहरण हैं।

ईश्वर एक है या अनेक अथवा उसका अस्तित्व है भी या नहीं, यह ऐसी अंतहीन बहस है, जिस पर सर्वस्वीकार्य मत कभी नहीं बन सकता, परंतु यह तय है कि केवल बहुईश्वरवाद ने देवत्व को नारी रूप में स्वीकारा है। प्रकृति पूजा को महत्व देने के कारण बहुईश्वरवाद ने अमूर्त, काल्पनिक, निराकार सत्ता के स्थान पर मूर्त, गोचर शक्तियों का आह्वान किया है। ईश्वर की अनेक रूप में स्वीकार्यता, सहिष्णुता और सामंजस्य को एक प्राकृतिक भाव बनाती है। ऐसा विश्वदर्शन पर्यावरण, लैंगिक असमानता और नस्लभेद जैसी समस्याएं नहीं उपजने देता। विश्व शांति और सौहार्द की बहाली में बहुईश्वरवाद की भूमिका महत्वपूर्ण है।

अमेरिकी मूलनिवासियों के भारी दबाव ने पिछले वर्ष ही पोप को 1452 में जारी 'डाक्ट्रिन आफ डिस्कवरी' का खंडन करने पर मजबूर किया। यूरोप के कैथोलिक साम्राज्यों द्वारा ''खोजी'' गई जमीनों पर उन्हें मालिकाना हक देने वाले इस अमानवीय अध्यादेश का खंडन आज जमीनी स्थिति तो नहीं बदल सकता, लेकिन यह देशज धर्मों की नैतिक जीत है। पश्चिमी देशों में बहुईश्वरवादी देशज धर्मों की ओर रुझान बढ़ा है। डेनमार्क, आइसलैंड और लिथुआनिया में तो ऐसे लोगों की अच्छी-खासी संख्या हो गई है। हालांकि देशज एवं बहुईश्वरवादी धर्मों के समक्ष अपना सम्मान और पुरातन गौरव पाने की लड़ाई अभी लंबी है। इस दिशा में विश्व भर के देशज धर्मों को साथ मिलकर साझा मंचों पर आने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी आबादी वाला बहुईश्वरवादी देश होने के नाते भारत से इस प्रयास के नेतृत्व की सदा अपेक्षा रहेगी।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

देश की तस्वीर बदलने वाली गारंटी

विवेक ठाकुर

मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में देश में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए और गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठा

विगत दस वर्षों में भारत एक बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव के दौर से गुजरा है। इसने देश को एक सक्षम राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर के माध्यम से भारतीय संस्कृति की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत यह बदलता समयचक्र भारत का होने वाला है। रामराज्य की संकल्पना को आत्मार्पित करने के साथ मोदी सरकार ने देश में कई जनकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया है, जिसके परिणामस्वरूप बीते एक दशक में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यह महज आंकड़ा नहीं है, बल्कि 25 करोड़ गरीबों के सशक्त होने की गारंटी है। नीति आयोग का कहना है कि अब पांच प्रतिशत गरीब ही बचे हैं। यह भारत की सामर्थ्य का सबसे बड़ा प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि देश में सिर्फ चार जातियां गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति हैं। इन्हें सशक्त और समृद्ध बनाने का प्रयास जारी है। आज देश में लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ चुकी हैं। स्वयं सहायता समूहों की इन महिलाओं को मोदी सरकार द्वारा आठ लाख करोड़ रुपये बैंक लोन और 40 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता अब तक प्रदान की जा चुकी है। चार करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर मिला है। एक समय पूर्ववर्ती सरकारों में गरीबों-वंचितों की कहीं सुनवाई तक नहीं होती थी, लेकिन मोदी सरकार में सभी स्वाभिमान के साथ जीवन-यापन कर रहे हैं। एससी-एसटी और वंचितों को उनका खोया आत्मसम्मान मोदी की सरकार में मिला है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से दस करोड़ से अधिक माताओं-बहनों को नया जीवन मिला है। किसानों को सम्मान निधि देकर उन्हें संबल प्रदान किया जा रहा है।

भारत का प्रत्येक व्यक्ति सशक्त और समृद्ध हो, यह प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। सच पूछिए तो मोदी की गारंटी देश की तकदीर और तस्वीर बदल रही है। यही वजह है कि तीसरी बार भी देशवासियों के मन में मोदी जी रमते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नीति और नीयत से समाज के अंतिम जन को विकास की मुख्यधारा से जोड़ दिया है। इसी का परिणाम है कि देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र देकर देश को एक नया सोच प्रदान किया है। इस सोच में तुष्टीकरण और जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। सामाजिक न्याय की इस नई परिभाषा को देश ने समय-समय पर स्वीकार किया है। संविधान निर्माताओं ने जिस समतामूलक समाज और जन-जन के कल्याण के लिए अलख जगाई थी, उसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने का कार्य मोदी सरकार में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भारत और भारतीयता के ध्वजवाहक हैं। वह देश की अस्मिता और सम्मान को वैश्विक फलक पर नया आयाम दिला रहे हैं। केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। आज देश के हर जरूरतमंद नागरिक को सरकारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। बेघरों को घर, गरीबों को राशन और मुफ्त उपचार मिल रहा है। बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगा है। सीधे बैंक खातों में लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं की राशि पहुंच रही है। युवाओं के सपनों को पंख लगे हैं और महिलाओं को उनके अधिकार मिल रहे हैं।

पीएम मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बनता देश। प्रेट्र

एक समय अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन का जो सपना देखा था, वह आज फलीभूत हो रहा है। यही वजह है कि समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूती मिल रही है। अयोध्या में राममंदिर के निर्माण के साथ देश के सांस्कृतिक गौरव का भी पुनरुत्थान हो रहा है। काशी-तमिल संगमम् का आयोजन उत्तर-दक्षिण की संस्कृति और संस्कार को समरसता प्रदान कर रहा है। चंद्रयान-3 की सफलता, जी-20 का सफल आयोजन संपन्न कराकर दुनिया को भारत ने यह संदेश दिया कि वह आज विश्वगुरु बनने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को नया संसद भवन भी मिला। नया संसद भवन नई उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। आत्मनिर्भर भारत और स्वाभिमानी भारत की नींव इसी नए संसद भवन से रखी जानी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू कर मोदी सरकार ने आधी आबादी को भी पूरा हक प्रदान किया। मातृ शक्ति के ऋणी हम सभी हैं और देश को विकसित और समृद्ध बनाने में उनकी भी महती और अग्रणी भूमिका रहने वाली है।

न्याय, बंधुत्व और समतावादी दृष्टिकोण अब संविधान में उल्लिखित पवित्र शब्द मात्र नहीं रह गए हैं। देश के लोगों को इनके वास्तविक अर्थों से परिचित कराने का काम मोदी सरकार ने किया है। वास्तव में मोदी सरकार का पहला और दूसरा कार्यकाल देश में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने तथा गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला रहा है। वर्षों से लंबित राष्ट्रीय महत्व के विषयों को सुलझाने वाला भी रहा है। लोगों को स्पष्ट दिख रहा कि भारत का भविष्य और विकसित राष्ट्र का सपना मोदी की गारंटी के बगैर संभव नहीं है। देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी गारंटी है। वह अगले पांच साल के कार्यकाल के विजन को स्पष्टता के साथ देश के सामने रख रहे हैं। इससे यह आस जगी है कि उनके नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। यही वजह है कि देश की जनता भी मोदी जी के तीसरे कार्यकाल को लेकर उत्साहित है और उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है।

(लेखक भाजपा के राज्यसभा के सदस्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अनुराग

अनुराग शब्द सुन या पढ़कर अधिकांश लोगों के मन में प्रायः प्रेम या प्रणय का भाव आता है। अनुराग हृदय से प्रस्फुटित हुआ एक ऐसा सोता है, जो जब फूटता है तो तन-मन को भिगो जाता है। मानव न जाने कितने प्रकार की भावनाओं से जीवन भर उलझता या आनंदित होता रहता है। सबसे सहज, सुंदर, आनंददायक भावना यदि है तो वह है प्रीति की, स्नेह की, अनुराग की। यह भावना केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। अनुराग में, प्रेम में अपनापन, धीरज, सद्भावना, समर्पण सब समाहित हैं। नारी तो उसी पल से अपने शिशु के प्रति अनुराग से भर जाती है जब वह उसके शरीर का भाग हो जाता है। माता-संतान के अनुराग का कोई पर्याय है ही नहीं। मानवीय रिश्ते अनुराग, प्रेम से ही एक-दूसरे से बंधे रह पाते हैं।

मनुष्य प्रतिपल सोचने-समझने की क्षमता रखता है। नए-नए आयामों की खोज उसे निरंतर गतिमान रखती है। इस खोज के चलते नवीन विचारों, कार्यों, आस्थाओं आदि के प्रति अनुराग की भावनाओं का उत्सर्जन होता है। किसी का कला के प्रति, खेलकूद के प्रति, अन्वेषण या कोई भी सृजनात्मक कार्य के प्रति इतना आकर्षण, अनुराग हो जाता है कि वह अपने लक्ष्य के प्रति समस्त जीवन तक दांव पर लगा देता है। उसका धैर्य, उसका मनोबल उसकी इच्छाशक्ति उसे अपनी निर्धारित राह से भटकने नहीं देती, तभी लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो पाता है। कितने ही महापुरुष वर्षों तक हिमालय के अंचलों में सत्य की खोज एवं ईश्वर के प्रति अनुराग में जीवन अर्पण कर देते हैं।

वास्तव में प्रेम, अनुराग के प्रतिफल की आशा ही सभी कष्टों की जड़ है। अंततः बिना स्वार्थ, इच्छा के ईश्वर के प्रति अनुराग ही मन को स्थिर, शांत रख पाने का एकमात्र उपाय है। यह सत्य जितना शीघ्र समझ आ जाए, उतना ही उचित है।

छाया श्रीवास्तव

वीआइपी संस्कृति पर लगाम आवश्यक

डा. मोनिका शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सड़क पर आम आदमी की तरह चलने का निर्णय वीआइपी संस्कृति पर लगाम लगाने की एक सार्थक पहल है

बीते दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री के काफिले का ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना वीआइपी संस्कृति पर लगाम लगाने की एक सार्थक पहल कहा जा सकता है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क पर आम आदमी की तरह चलने का निर्णय किया है। ऐसे में अब उनका काफिला रेड सिग्नल पर आम लोगों की तरह ही रुकेगा। आमजन को मुख्यमंत्री के काफिले की वजह से होने वाली परेशानी से बचाने के लिए यह निर्णय किया गया है।

भारत में आज भी वीआइपी संस्कृति ने गहरी जड़ें जमा रखी हैं। आम और खास के बीच खाई बनाते बहुत से तौर-तरीकों के कारण जनमानस में शिकायत ही नहीं, आक्रोश का भाव भी रहता है। देश के हर हिस्से में अति विशिष्ट लोगों की आवाजाही के दौरान बार-बार लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोग अनगिनत समस्याएं झेलते हैं। घंटों तक जाम में फंसना देश की उन्नति में भागीदार बनने वाली जनता का समय और ऊर्जा दोनों छीनता है। यहां तक कि एंबुलेंस के जाम में फंसने के भी समाचार आते रहते हैं। कितने ही मोर्चों पर वीआइपी संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाली बातें, व्यवहार और सार्वजनिक स्थलों पर आवाजाही आम लोगों के लिए मुसीबत बनती हैं। ये बंदिशें जनमानस को कमतर तो महसूस करवाती ही हैं, बहुत सी परेशानियां भी खड़ी करती हैं। ऐसी स्थितियां आमजन को निराशा, असुरक्षा और असहजता का अनुभव करवाती हैं। ऐसे में आवश्यक है कि जनमानस को जाम से छुटकारा दिलाने और गंभीर मरीजों को जोखिम से बचाने के लिए न केवल ऐसे निर्णय लिए जाएं, बल्कि योजनागत रूप से इनपर अमल भी किया जाए।

कहना गलत नहीं होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले हमारे देश में जनता की सहज सी समस्याओं को समझने में भी कोताही की जाती है। इतना ही नहीं उन परेशानियों से निजात दिलाने का मार्ग ढूंढ़ने के भी प्रयास नहीं किए जाते, जो केवल समानता के भाव को बल देने भर से हल हो सकती हैं। वीआइपी संस्कृति पर लगाना ऐसा ही एक रास्ता है। तकलीफदेह है कि राजनीति हो या कोई अन्य क्षेत्र, अति विशिष्ट लोगों की सहजता को प्राथमिकता देने की संस्कृति आमजन के लिए असहजता पैदा करने का कारण बनी हुई है। इसीलिए आम और खास की दूरी पाटने के लिए हर स्तर पर वीआइपी संस्कृति से मुक्ति पाना आवश्यक है। जन-प्रतिनिधियों को खुद ही इस विशिष्टता की मानसिकता से दूरी बनाकर जनहित को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे में एक मुख्यमंत्री का स्वयं आम आदमी की तरह ही ट्रैफिक नियमों का पालन करना वाकई सुखद पहल है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

लोकतंत्र की मजबूती के लिए करें मतदान

'मतदाताओं की जिम्मेदारी' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। मतदान में मतदाता जिम्मेदारी निभाने के लिए लंबी-लंबी कतारों में लगकर अपने कीमती मत का प्रयोग करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अधिकांश राजनेता चुनाव जीत जाने के बाद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। अगर निभाते होते तो आमजन को मूलभूत सुविधाओं के लिए न तरसना पड़ता। उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि से परेशान न होना पड़ता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी मजबूती के लिए चुनाव में आमजन की भागीदारी जरूरी है। दुख इस बात का है कि कुछ स्वार्थी लोगों के राजनीति में आ जाने और राजनीति के अवसरवाद की ओर अग्रसर होने के कारण आमजन का विश्वास कुछ कमजोर हो रहा है। अक्सर आमजन को यह कहते सुना जाता है कि हम किसी को अपना कीमती वोट क्यों दें, क्योंकि सत्ता में आने के बाद वे हमारी समस्याओं की अनदेखा करते हैं। यह हकीकत भी है कि ज्यादातर नेता चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की जनता को भूल जाते हैं। वहीं जो मतदाता चुनावों में जाति-धर्म में बहक कर अपने कीमती मत का प्रयोग करते हैं वे भी लोकतंत्र को कमजोर करते ही हैं। अपने और भावी पीढ़ी के भविष्य को खराब करते हैं। चुनावों में अगर किसी गलत उम्मीदवार को वोट दे दिया जाता है तो ऐसा उम्मीदवार चुनाव जीत जाने के बाद अपने निजी स्वार्थ को ही पांच साल तक सर्वोपरि रखता है, आमजन की परवाह नहीं करता है। इसलिए चुनावों में मतदाताओं को मतदान करते समय समझदारी से काम लेना चाहिए। सही उम्मीदवार को चुनकर अपने प्रदेश और देश की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, नहीं तो पांच साल तक पछतावे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मेलबाक्स

पेपर लीक की बीमारी

'परीक्षा में सेंधमारी' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में सरकार की सख्ती के बावजूद विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में होने वाले पेपर लीक पर जो चिंता व्यक्त की गई है, वह विचारणीय है। भर्ती परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता न करने की प्रतिबद्धता के चलते उप्र की योगी सरकार को पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को रद कर पुनः परीक्षा कराने का निर्णय लेना पड़ा। पेपर लीक की पुष्टि के बाद प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय तो है, लेकिन क्या इससे प्रतिभाशाली युवाओं के साथ होने वाले खिलवाड़ पर लगाम लग पाएगी? परीक्षा निरस्तीकरण से क्या प्रतिभागियों के बहुमूल्य समय के साथ उस मेहनत की भरपाई हो पाएगी, जो उन्होंने इस पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए की थी? आखिर इन परीक्षार्थियों का दोष क्या है, जो इनको पुनः उसी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी, जो एक बार वह दे चुके हैं? ऐसे अनेक प्रश्न हैं, जो भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की लाइलाज बीमारी से उभर कर आते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले 2017 में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। 2018 में यूपीपीसीएल और ट्यूबवेल ड्राइवर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। 2021 में भी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा इस पेपर लीक बीमारी की चपेट में आ गई थी। इससे सबक लेकर यदि 2024 की यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को फूलप्रूफ बनाने के कारगर उपाय किए गए होते तो आज लाखों युवाओं को दोबारा परीक्षा देने की नौबत नहीं आती। ऐसे में प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून का सहारा लेते हुए एक ऐसा तंत्र विकसित करने की जरूरत है, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को पेपर लीक की लाइलाज बीमारी से मुक्त कर सके। पेपर लीक का पाप प्रतिभाशाली परीक्षार्थियों के प्रति किया जाने वाला महापाप है। इसमें संलिप्त अपराधियों को हर हाल में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

डा. वीपी पांडेय, अलीगढ़

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****